*अर्थव्यवस्था की स्थिति**

वैश्विक अर्थव्यवस्था नाजुक भू-राजनीतिक और आपूर्ति श्रृंखलाओं के दबावों से उत्पन्न होने वाली बढ़ती अनिश्चितताओं के साथ-साथ चल रही है। घरेलू अर्थव्यवस्था ने बाह्य अनिश्चितताओं को अच्छी तरह से पार किया है, जो स्वस्थ मांग की स्थिति और औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के आघात-सहनीय प्रदर्शन के आधार पर है। जून में हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई, जबकि मुख्य मुद्रास्फीति, विशेष रूप से कीमती धातुओं को छोड़कर कम रही। चलनिधि की स्थिति में और सुधार हुआ, जिससे चल रही मजबूत ऋण वृद्धि का समर्थन हुआ। विदेशी निवेश के प्रवाह से सहायता प्राप्त होने के दृष्टिकोण में सुधार के साथ भारत का बाह्य क्षेत्र स्थिर बना हुआ है।

भूमिका

वैश्विक अर्थव्यवस्था उच्च अनिश्चितता के साथ एक उथल-पुथल भरे दौर से गुजर रही है। पश्चिम एशिया में युद्धविराम वार्ता के खत्म होने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क को फिर से उथल-पुथल में डाल दिया है, जिससे सुधार में बाधा आ गई है। कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) के नेतृत्व वाले तकनीकी परिवर्तन और संबंधित निवेश वैश्विक अर्थव्यवस्था का समर्थन करना जारी रखे हुए हैं। जून के माध्यम से पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की संभावनाओं ने बाज़ारों और व्यावसायिक अपेक्षाओं को स्थिर करने में मदद की, हालांकि जुलाई की शुरुआत में शांति व्यवस्था के पतन के साथ संघर्ष विराम अल्पकालिक रहा, जिससे वैश्विक व्यापार और मुद्रास्फीति के जोखिमों के परिदृश्य को अनिश्चितता के क्षेत्र में वापस धकेल दिया गया। इसके अलावा, एआई और प्रौद्योगिकी से संबंधित शेयरों में अस्थिरता भी देर से बढ़ी है, जिससे वित्तीय बाजारों के सामने अनिश्चितताएं बढ़ गईं।

पश्चिम एशिया में युद्ध के आर्थिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, जो वैश्विक प्रौद्योगिकी चक्र में सकारात्मक गति से आंशिक रूप संतुलित हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने जुलाई 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट में, 2026 के लिए अपने वैश्विक विकास पूर्वानुमान को अपने अप्रैल अनुमानों के सापेक्ष 10 आधार अंकों तक संशोधित किया। वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति भी 2025 में 4.1 प्रतिशत से बढ़कर 2026 में 4.7 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो आपूर्ति बाधाओं से लगातार मूल्य दबाव को दर्शाती है।

जून के लिए उच्च-आवृत्ति संकेतक वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में आघात-सहनीयता का सुझाव देते हैं। अप्रैल और मई में स्थिर रहने के बाद, जून में वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) का विस्तार हुआ क्योंकि सेवा गतिविधियों में मजबूती आई। कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक और औद्योगिक धातुओं की कीमतों के साथ कमोडिटी की कीमतों में गिरावट आई, जो जुलाई की शुरुआत में बड़े पैमाने पर अपने पूर्व-संघर्ष स्तर पर वापस आ गए। हालांकि, पश्चिम एशिया में तनाव में एक नए सिरे से भड़कने ने ऊर्जा बाज़ारों में अनिश्चितता वापस ला दी है, जिसमें कच्चे तेल की कीमतें मजबूत हो गई हैं।

जून में तनाव कम होने और कच्चे तेल की कीमतें घटने की संभावनाओं के चलते वैश्विक इक्विटी बाज़ार में तेज़ी आई। हालांकि, मूल्यांकन चिंताओं पर प्रौद्योगिकी शेयरों में नए सिरे से संघर्ष और सुधार की आशंका के बीच जुलाई में बाज़ार अस्थिर हो गए। जून में 10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल अधिक रहा; कम मुद्रास्फीति के आंकड़ों की प्रतिक्रिया में सहजता से पहले सख्त मौद्रिक नीति की अपेक्षाओं के बीच जुलाई की शुरुआत में यह और सख्त हो गया। केंद्रीय बैंक की कार्रवाइयां विकास-मुद्रास्फीति संतुलन के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं में अलग-अलग हो गईं।

जून में घरेलू अर्थव्यवस्था में तेजी बनी रही। मांग की स्थिति स्वस्थ रही, ग्रामीण मांग में तेजी और दृढ़ शहरी मांग

* इस आलेख को राजीब दास, राधेश्याम वर्मा, ऋषभ कुमार, विश्वजीत मोहंती, दुर्गा जी, ऊर्जा यादव, अमीन अशरफ, विकास आनंद, भाग्यश्री चटोपाध्याय, नीलावा दास, अनुपम कुमार, ऐट्टम अभिग्नू यादव, राशिका अरोड़ा, साक्षी चौहान, सार्थक गुलाटी, शिवम, पारस, अंजना साहा, श्रेया भान, श्रीजित टी. बी., अमित पवार, सुप्रियो मोंडल, समृद्धि, अथिरा सी. ए., पलक गोयल और सौरभ शर्मा द्वारा तैयार किया गया है। डॉ. पूनम गुप्ता, डिप्टी गवर्नर, और श्री संजय हंसदा, कार्यपालक निदेशक द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और टिप्पणियों के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया जाता है। सिद्धार्थ नाथ, सौमश्री तिवारी और विद्या द्वारा की गई सहकर्मी समीक्षा के लिए उनका धन्यवाद व्यक्त किया जाता है। इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और यह भारत के रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

से समर्थन मिला। उच्च आवृत्ति संकेतक मजबूत औद्योगिक प्रदर्शन और एक आघात-सहनीय सेवा क्षेत्र का सुझाव देते हैं। प्रचलित अल नीनो स्थितियों के बीच दक्षिण-पश्चिम मानसून में असमान प्रगति के कारण खरीफ की बुवाई में देरी हुई है। उच्च सार्वजनिक खाद्यान्न स्टॉक को मूल्य दबावों की वजह कुछ राहत प्रदान करनी चाहिए। बाहरी व्यापार में गति बनी हुई है जैसा कि ति1:2026-27 में निर्यात और आयात में उच्च वृद्धि में परिलक्षित होता है।

खाद्य और ईंधन घटकों के कारण जून में हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। हालांकि, कोर (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) मुद्रास्फीति अपरिवर्तित रही। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति जून में बढ़ गई।

अप्रैल-मई 2026-27 के दौरान केंद्र का राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक था, जबकि राज्यों के राजकोषीय घाटे में गिरावट आई।

जून की दूसरी छमाही में प्रणाली चलनिधि कम हो गई। जुलाई के पहले पखवाड़े में कर बहिर्वाह के दबाव और महीने के अंत में सख्ती से पहले तेजी से सरकारी व्यय के बीच इसमें सुधार हुआ। भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) जून में नीतिगत कॉरिडोर के ऊपरी सीमा में रही और जुलाई में नीतिगत दर की ओर बढ़ गई। पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम वार्ता के टूटने के बाद सुधार से पहले 91-दिवसीय ट्रेजरी बिल, 3 महीने के वाणिज्यिक कागजात, जमा प्रमाण पत्र और दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल भी जून में और जुलाई की शुरुआत में कम हो गया।

सकल और निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) पिछले वर्ष की तुलना में अप्रैल-मई 2026 में अधिक था। निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाह जून में सकारात्मक हो गया और नीतिगत समर्थन और भू-राजनीतिक तनाव को कम करने के बीच जुलाई में सकारात्मक प्रवाह बनाए रखा। जून में भारतीय इक्विटी बाजारों में तेजी आई। हालांकि, जुलाई की शुरुआत में युद्धविराम की समाप्ति के बाद, इक्विटी बाज़ार सीमा में रहे।

भारत के प्रमुख बाह्य क्षेत्र की भेद्यता संकेतक मार्च 2026 के अंत तक अच्छी तरह से स्थिर रहे। विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त बना रहा। अमेरिकी डॉलर की मजबूती को देखते हुए, भारत सहित प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) की मुद्राओं में जुलाई में गिरावट आई।

आलेख का शेष भाग चार खंडों में प्रस्तुत किया गया है। खंड II वैश्विक अर्थव्यवस्था में उभरते विकास को कवर करता है। खंड III घरेलू व्यापक आर्थिक स्थितियों का आकलन प्रदान करता है। खंड IV भारत में प्रचलित वित्तीय स्थितियों को प्रस्तुत करता है, जबकि खंड V में निष्कर्ष है।

II. वैश्विक स्थितियाँ

आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के लिए अपने जुलाई 2026 अपडेट में, अप्रैल 2026 में अपने अनुमानों की तुलना में 2026 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को 10 आधार अंकों की गिरावट से संशोधित किया, जो पश्चिम एशिया संघर्ष के प्रतिकूल प्रभावों को दर्शाता है, आंशिक रूप से मजबूत एआई-संचालित निवेश से संतुलित होता है। वर्ष 2027 में वृद्धि अधिक होने का अनुमान है। हालाँकि, देशों में असममित सुधार हो सकता है (सारणी II.1)। वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति वर्ष 2025 में 4.1 प्रतिशत से बढ़कर 2026 में 4.7 प्रतिशत और 2027 में घटकर 3.9 प्रतिशत होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, विकास के दृष्टिकोण के लिए जोखिम में कमी दिखाई देती है, पश्चिम एशिया में नए सिरे से तनाव की संभावनाओं, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में संबंधित व्यवधानों और निरंतर मुद्रास्फीति के दबाव से घिरा हुआ है।

जून से भू-राजनीतिक जोखिम में कमी आई, जो पश्चिम एशिया में कूटनीतिक प्रयासों में निरंतर प्रगति द्वारा समर्थित था

सारणी II.1: आईएमएफ: चुनिंदा एई और ईएमडीई के जीडीपी की वृद्धि का अनुमान

अनुमान	2026		2027	
अनुमान का महीना	अप्रैल 2026	जुलाई 2026	अप्रैल 2026	जुलाई 2026
विश्व	3.1	3.0	3.2	3.4
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं (एई)	1.8	1.7	1.7	1.8
अमेरिका	2.3	2.3	2.1	2.2
यूके	0.8	1.0	1.3	1.3
यूरो क्षेत्र	1.1	0.9	1.2	1.2
जापान	0.7	0.6	0.6	0.7
उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं (ईएमडीई)	3.9	3.8	4.2	4.5
उभरता हुआ बाजार और विकासशील यूरोप	2.0	1.9	2.1	2.1
रूस	1.1	1.1	1.1	1.1
उभरता हुआ और विकासशील एशिया	4.9	5.0	4.8	4.8
भारत#	6.5	6.4	6.5	6.7
चीन	4.4	4.6	4.0	4.1
लैटिन अमेरिका और कैरिबियन	2.3	2.4	2.7	2.7
मेक्सिको	1.6	1.2	2.2	1.9
ब्राज़ील	1.9	2.4	2.0	2.2
मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका	1.9	0.7	4.6	6.5
सब-सहारा अफ्रीका	4.3	4.3	4.4	4.5
दक्षिण अफ्रीका	1.0	1.1	1.3	1.3

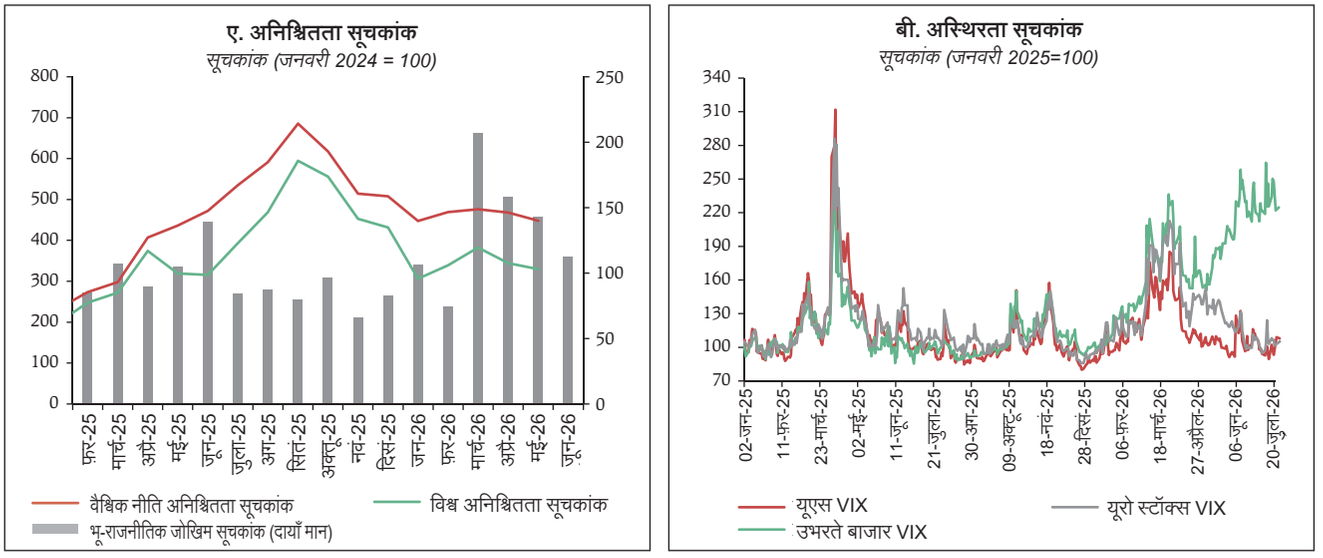
टिप्पणी: #: भारत का डेटा वित्तीय वर्ष के आधार (अप्रैल-मार्च) पर है, जबकि अन्य सभी देशों के लिए यह कैलेंडर वर्षों के लिए है।
स्रोत: आईएमएफ का विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट, जुलाई 2026.

(चार्ट II.1ए)। यह ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक व्यापार पर चिंताओं को कम करने में परिलक्षित हुआ। हालांकि, ईएमई में वित्तीय बाज़ार में अस्थिरता जुलाई की शुरुआत में उच्च अमेरिकी भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच पूंजी बहिर्वाह के कारण टिक गई। इसके विपरीत, अस्थिरता काफी हद तक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में निहित रही, जो मजबूत आय, मुद्रास्फीति की चिंताओं को कम करने और सुरक्षित पूंजी प्रवाह द्वारा समर्थित थी (चार्ट II.1बी)।

जून के उत्तरार्ध में होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से यातायात में थोड़ा सुधार देखा गया, जिसमें अमेरिका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के बाद जहाज पारगमन लगभग शून्य स्तर से फिर से उबरता हुआ दिखा (चार्ट II.2)। हालांकि, रुक-रुक कर होने वाली झड़पों और बाद में जुलाई में अमेरिका-ईरान शांति समझौते के पतन ने सामान्य स्थिति में वापसी को रोक दिया।

वैश्विक उत्पादन, जैसा कि समग्र पीएमआई में परिलक्षित होता है, अप्रैल-मई 2026 के दौरान स्थिर रहने के बाद जून

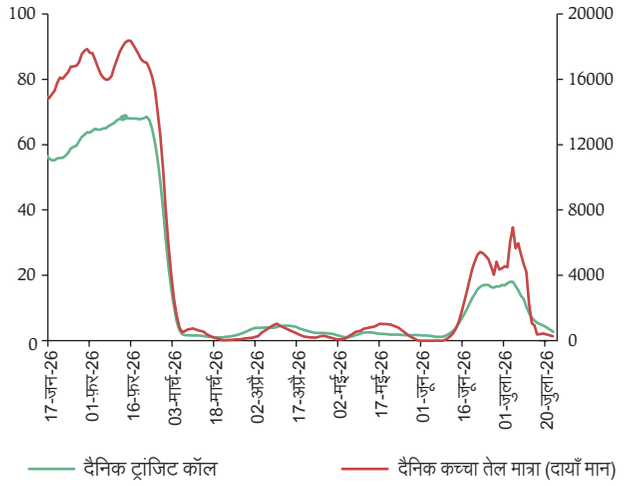
चार्ट II.1: ईएमई के लिए वित्तीय बाज़ार में उतार-चढ़ाव में बढ़ोतरी



स्रोत: ब्लूमबर्ग: www.PolicyUncertainty.com; और वैश्विक अस्थिरता सूचकांक डेटाबेस।

चार्ट II.2: होर्मुज जलडमरूमध्य से रोज़ाना ट्रांज़िट कॉल्स और ट्रांज़िट कच्चे तेल की मात्रा

(जहाज प्रतिदिन, बायां मान; प्रतिदिन हज़ार बैरल, दायां मान)



स्रोत: ब्लूमबर्ग।

में विस्तार हुआ। विनिर्माण, जिसने पश्चिम एशिया संघर्ष की शुरुआत के बाद से सेवाओं से बेहतर प्रदर्शन किया था, सभी ने इन्वेंट्री चक्र में बदलाव के कारण अपनी वृद्धि को थोड़ा कम देखा।[1] सेवा गतिविधि मजबूत हुई, कम ऊर्जा की कीमतों से समर्थित परिचालन लागत को कम करने से उपभोक्ता-सेवा उद्योगों को लाभ हुआ। नए निर्यात ऑर्डर कम रहे, जो दबे हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण की दृढ़ता को दर्शाता है (सारणी II.2)।

भारत और चीन जैसे प्रमुख ईएमई, अनुक्रमिक कमी के बावजूद, जून में समग्र उत्पादन के मामले में एई की तुलना में तेजी से बढ़े (चार्ट II.3 ए)। नए निर्यात ऑर्डर ज्यादातर संकुचन में रहे, जिसमें भारत, दक्षिण अफ्रीका, जापान और इटली उल्लेखनीय अपवाद रहे (चार्ट II.3 बी)।

कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक और धातु की कीमतों से प्रेरित जून में कमोडिटी की कीमतों में कमी आई। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स ने पश्चिम एशिया में विकसित भू-राजनीतिक विकास को प्रतिबिंबित किया (चार्ट II.4)।

सारणी II.2: वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक

	जून-25	जुला-25	अग-25	सितं-25	अक्टू-25	नवं-25	दिसं-25	जन-26	फर-26	मार्च-26	अप्रै-26	मई-26	जून-26
पीएमआई समग्र	51.7	52.5	52.9	52.5	53	52.7	52	52.5	53.3	51.0	51.8	51.8	52.0
पीएमआई विनिर्माण	50.4	49.7	50.9	50.7	50.9	50.5	50.4	50.9	51.8	51.3	52.6	52.6	52.2
पीएमआई सेवाएं	51.8	53.5	53.3	52.9	53.5	53.2	52.4	52.8	53.4	50.8	51.2	51.3	51.7
पीएमआई निर्यात आदेश	49.1	48.5	48.9	49.7	48.5	49.9	49.3	49.7	51.2	49.6	49.6	48.9	49.2
पीएमआई निर्यात आदेश: विनिर्माण	49.2	48.2	48.7	49.5	48.3	49.9	49.1	49.9	51.4	50.0	50.2	49.6	49.4
पीएमआई निर्यात आदेश: सेवाएं	48.7	49.4	49.3	50.2	49.4	50.2	49.6	48.9	50.5	48.3	47.6	46.6	48.3

50

<<<<<<संकुचन----------विस्तार>>>>>>

टिप्पणियां: 1. क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई), एक विसरण सूचकांक है, जो पिछले महीने की तुलना में प्रत्येक चर में हुए परिवर्तन को दर्शाता है और यह नोट करता है कि प्रत्येक बढ़ा/सुधरा है, घटा/बिगड़ा है या अपरिवर्तित रहा है। 50 से अधिक का पीएमआई मान विस्तार को दर्शाता है; 50 से कम संकुचन को दर्शाता है; और 50 के बराबर 'कोई परिवर्तन नहीं' को दर्शाता है।

2. अप्रैल 2023 के बाद के आंकड़ों पर हीट मैप लागू किया गया है। मैप में रंगों का इस्तेमाल किया गया है – लाल रंग प्रत्येक पीएमआई श्रृंखला में न्यूनतम मान को दर्शाता है, पीला रंग 50 (या कोई परिवर्तन नहीं वाला मान) को दर्शाता है, और हरा रंग उच्चतम मान को दर्शाता है।

स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

[1] "वैश्विक पीएमआई निरंतर उत्पादन वृद्धि में उछाल दिखाता है, लेकिन भविष्य की आशावादिता समाप्त हो रही है", एस एंड पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस, 01 जुलाई, 2026 (यहां उपलब्ध है: https://www.spglobal.com/market-intelligence/en/news-insights/research/2026/07/global-pmi-shows-sustained-manufacturing-growth-surge-but-future-optimism-fades).

चार्ट II.3 क्रय प्रबंधक सूचकांक : विभिन्न क्षेत्रों में तुलना

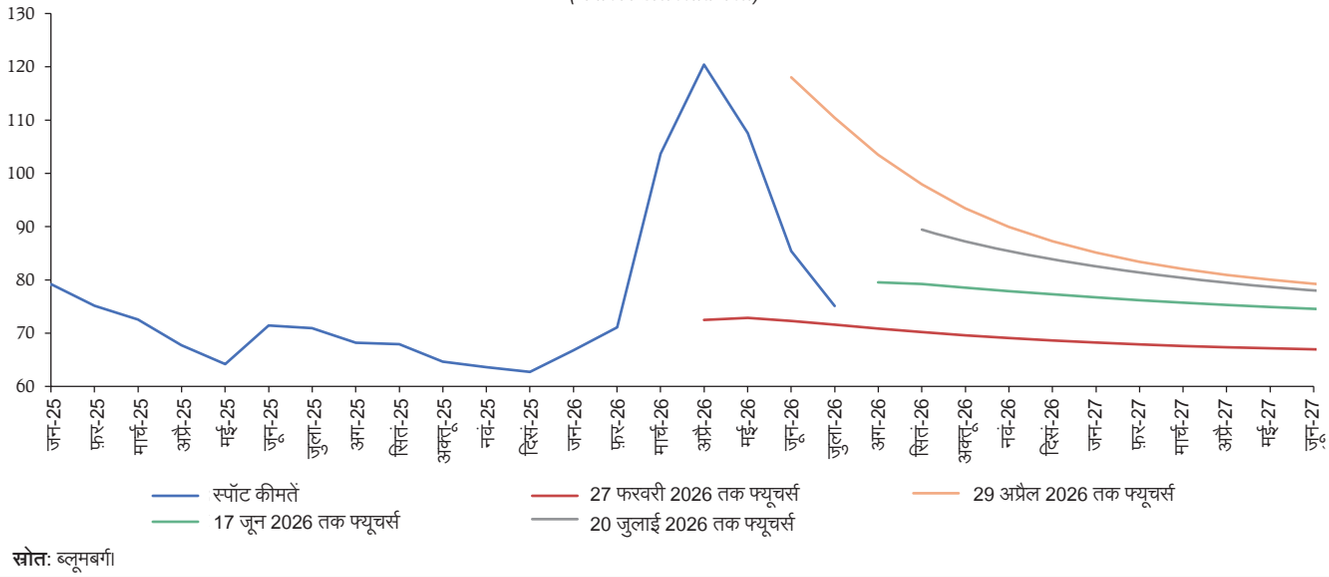


टिप्पणी: 50 का स्तर इक्विटि में कोई बदलाव नहीं दिखाता है, जबकि 50 से ऊपर की रीडिंग बढ़ोतरी का और 50 से नीचे की रीडिंग कमी का संकेत देती है।
स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) खाद्य मूल्य सूचकांक जून में चीनी, अनाज और डेयरी उत्पादों की कीमतों में कमी के साथ-साथ वनस्पति तेलों और मांस की कीमतों में वृद्धि के कारण लगभग स्थिर रहा। उच्च ब्याज दरों और मजबूत अमेरिकी डॉलर की उम्मीदों के बीच जुलाई में स्वर्ण की कीमतों में कमी जारी रही (चार्ट II.5ए और बी)।

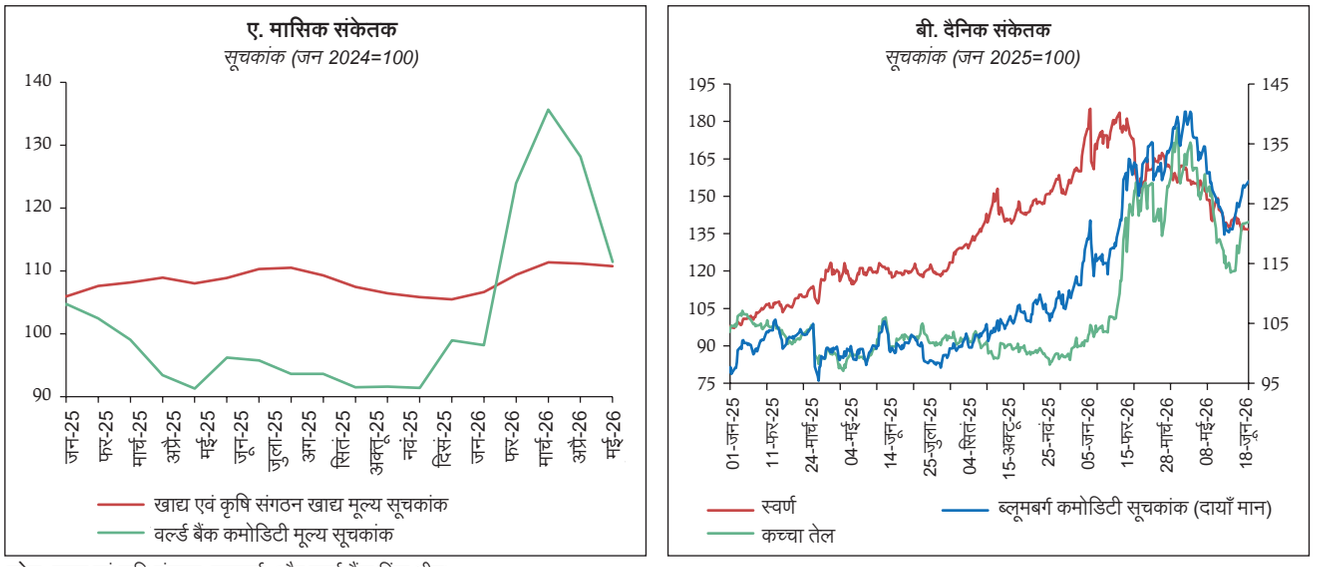
जुलाई की शुरुआत में कच्चे तेल, खाद्य और औद्योगिक धातुओं जैसी वस्तुओं की कीमतें संघर्ष से पहले के स्तर पर

चार्ट II.4 : ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें : स्पॉट और फ्यूचर्स



स्रोत: ब्लूमबर्ग।

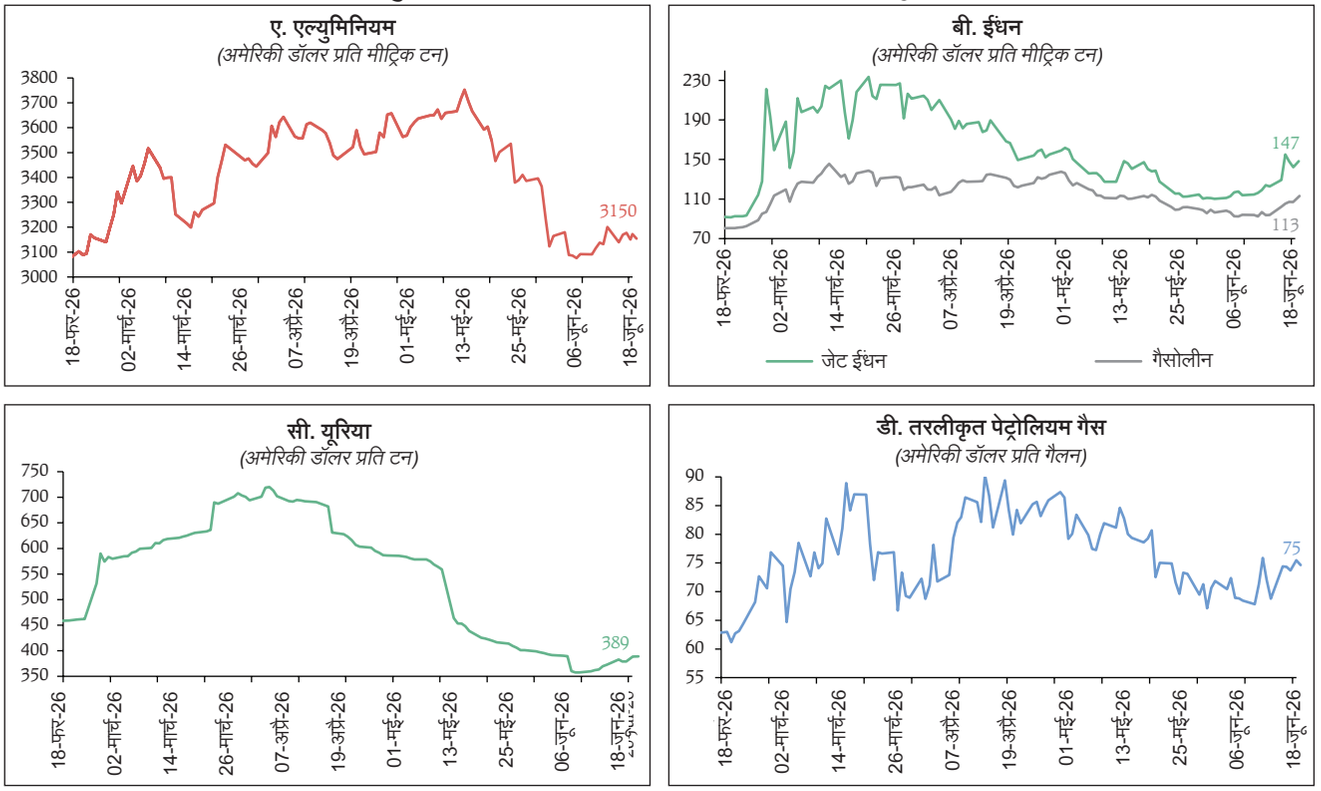
चार्ट II.5: वस्तुओं की कीमतों में कमी



स्रोत: खाद्य एवं कृषि संगठन; ब्लूमबर्ग; और वर्ल्ड बैंक पिंक शीट।

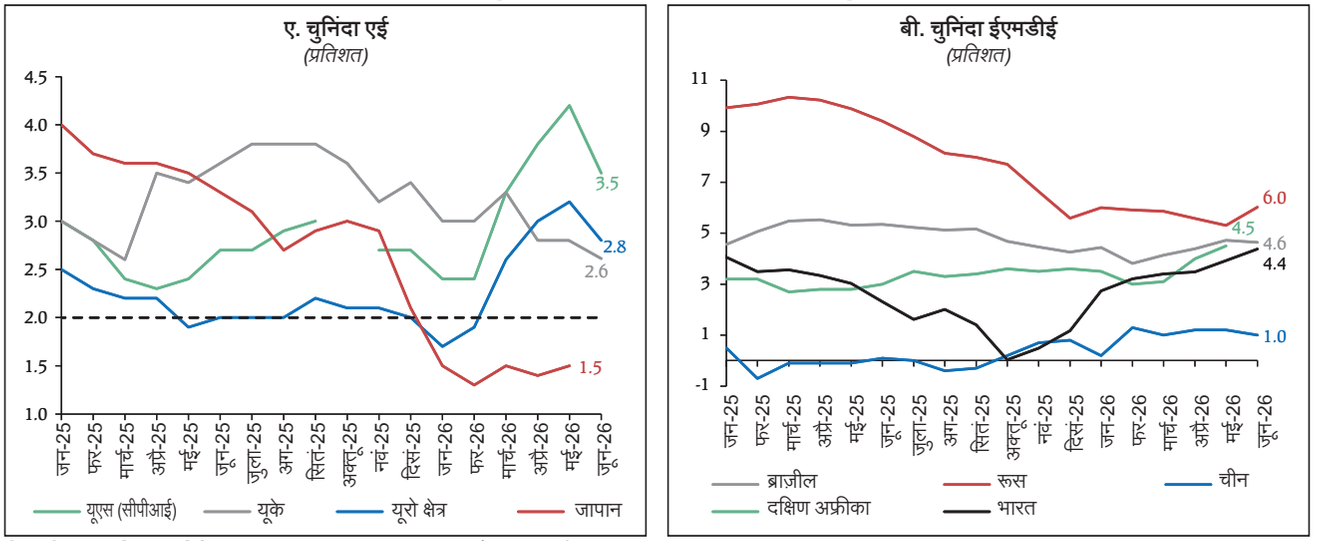
आ गईं, जिससे महीनों से जमा हुआ भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम काफी हद तक कम हो गया (चार्ट II.6)। हालांकि, पश्चिम एशिया में फिर से बढ़े तनाव ने वैश्विक कमोडिटी बाज़ार में, खासकर ऊर्जा की कीमतों के मामले में, अनिश्चितता बढ़ा दी।

चार्ट II.6: जुलाई में कमोडिटी की कीमतों में गिरावट की प्रवृति में बदलाव



टिप्पणी: डेटा नीचे दिए गए बेंचमार्क संविदा और कीमत सूचकांक के बारे में है: एलएमई एल्युमिनियम 3-महीने के फ्यूचर्स; सिंगापुर जेट केरोसीन और सिंगापुर गैसोलीन स्पॉट कीमतें; यूरिया यूएस गल्फ फ्यूचर्स; और मॉन्ट बेल्वियू प्रोपेन फिक्स्ड प्राइस फ्यूचर्स (एलपीजी)।
स्रोत: ब्लूमबर्ग।

चार्ट II.7: प्रमुख एई और ईएमई में हेडलाइन मुद्रास्फीति



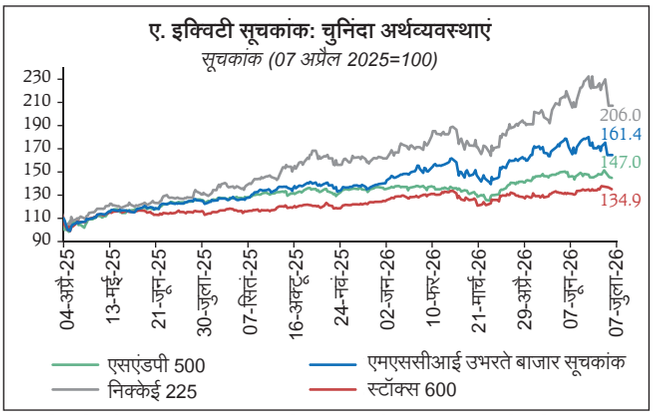
टिप्पणी: अमेरिकी मुद्रास्फीति डेटा श्रृंखला में यह ब्रेक इस समय के दौरान सरकारी शटडाउन के कारण है।
स्रोत: ब्लूमबर्ग: और ओईसीडी।

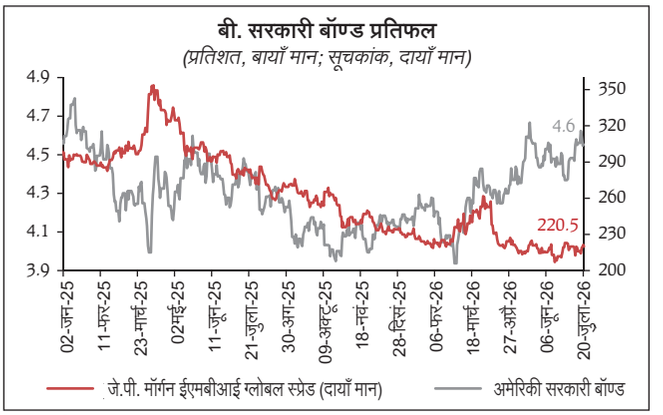
प्रमुख एई और ईएमई में मुद्रास्फीति जून में अधिक बनी रही। प्रमुख एई में, अमेरिका में मुद्रास्फीति गैसोलीन की कीमत के सामान्यीकरण के कारण कम हो गई। यूरो क्षेत्र में, ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत में गिरावट ने हेडलाइन मुद्रास्फीति को कम कर दिया। यूके में मुद्रास्फीति कम हो गई, जिसके कारण परिवहन लागत में गिरावट आई। जापान में, सरकारी ईंधन सब्सिडी की समाप्ति के बाद मई में मुद्रास्फीति में वृद्धि देखी गई (चार्ट II.7ए)। ईएमई में, ब्राजील में मुद्रास्फीति मामूली रूप से नरम हो गई, जो कम खाद्य और पेय पदार्थों और आवास की कीमतों से प्रेरित थी। ऊर्जा और कमोडिटी की कीमतों में ढील ने चीन में मुद्रास्फीति को सौम्य रखा। हालाँकि, रूस में मुद्रास्फीति बढ़ी, जिसका कारण गैसोलीन में कमी रही (चार्ट II.7बी)।

जून में अमेरिका-ईरान शांति वार्ता में प्रगति और कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बाद भू-राजनीतिक तनाव को कम करने के कारण इक्विटी बाजारों में आम तौर पर तेजी आई। जुलाई की शुरुआत में प्रौद्योगिकी शेयरों में बिकवाली और पश्चिम एशिया में नए सिरे से भू-राजनीतिक तनाव के कारण बाजार अस्थिर हो गए। जुलाई की शुरुआत में स्थिर होने से पहले, उच्च ब्याज दर की उम्मीदों और टेक शेयरों में लाभ बुकिंग के बीच जून में एसएंडपी 500 नीचे आ गया। यूरो क्षेत्र के इक्विटी ने जून और जुलाई की शुरुआत में अपनी ताकत बनाए रखी, जिसमें औद्योगिक, वित्तीय और रक्षा शेयरों में लाभ का विस्तार हुआ। निक्केई 225 ने जुलाई की शुरुआत में वैश्विक प्रौद्योगिकी बिकली, मुद्रा की अस्थिरता और वैश्विक व्यापक आर्थिक अनिश्चितता पर दो-तरफ़ा उतार-चढ़ाव दिखाने से पहले जून में सकारात्मक प्रतिलाभ दर्ज किया। उभरते बाजार इक्विटी ने जून के अंत में एआई रैली के बाद लाभ बुकिंग पर अपने सर्वकालिक उच्च स्तर से सुधार किया। जुलाई में गिरावट और गहरी हो गई, जो अमेरिका-ईरान शांति समझौते के पतन पर चिंताओं की वजह से है (चार्ट II.8ए)।

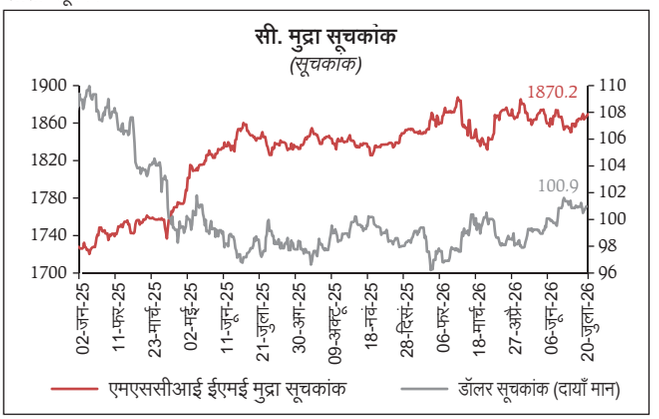
जून के दौरान, अस्थिरता का प्रदर्शन करते हुए अमेरिकी 10-वर्षीय ट्रेजरी प्रतिफल अधिक रहा। कम मुद्रास्फीति के आंकड़ों के जवाब में ढील देने से पहले एक सख्त मौद्रिक नीति की अपेक्षाओं के बीच जुलाई की शुरुआत में यह और सख्त हो गया (चार्ट II.8बी)। अमेरिकी डॉलर सूचकांक जून के दौरान मजबूत हुआ, लेकिन जुलाई में लाभ कम हो गया, जो मुद्रास्फीति

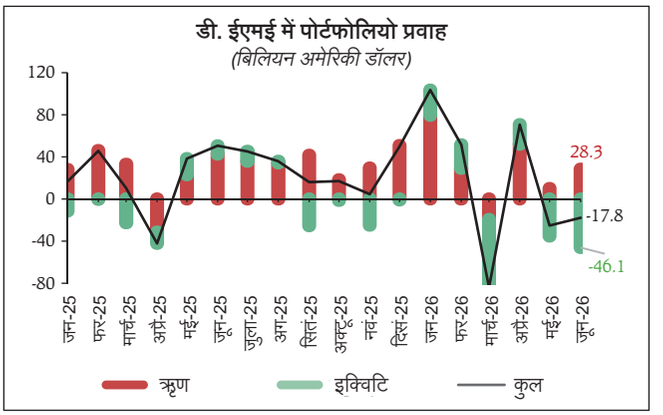
चार्ट II.8 वैश्विक वित्तीय बाज़ार





टिप्पणी: इक्विटी बाजारों को अमेरिका के लिए एस एंड पी 500, जापान के लिए निक्केई 225 और यूरोप के लिए स्टॉक्स 600 द्वारा दर्शाया गया है।
स्रोत: ब्लूमबर्ग





स्रोत: ब्लूमबर्ग: और इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस।

को कम करने से प्रेरित था (चार्ट II.8सी)। विदेशी निवेशकों ने जून में उभरते बाजार इक्विटी में जोखिम कम कर दिया, जबकि ऋण प्रवाह आंशिक रूप से बिकवाली की भरपाई करता है (चार्ट II.8डी)।

केंद्रीय बैंकों के नीतिगत निर्णय जून में अलग-अलग लेकिन सतर्क रहे (चार्ट II.9)। बढ़ते मुद्रास्फीति के दबावों के बीच, यूरो क्षेत्र और जापान ने नीतिगत दरों में वृद्धि की और आगे मौद्रिक सख्ती का संकेत दिया। अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने नीतिगत दरों को बनाए रखा। ईएमई में, रूस और ब्राजील ने नीतिगत दरों को कम कर दिया जबकि इंडोनेशिया और फिलीपींस ने दरें बढ़ा दीं। मेक्सिको और थाईलैंड ने नीतिगत दरों को आयोजित किया। जुलाई में, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया ने मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करने के लिए अपनी बेंचमार्क ब्याज दरों में वृद्धि की, जबकि मलेशिया और कनाडा ने स्थिर कीमतों और लचीली आर्थिक वृद्धि को देखते हुए अपनी एकदिवसीय नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा। चीन ने अपनी नीतिगत दर को बनाए रखा, जो पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच सावधानी को दर्शाता है।

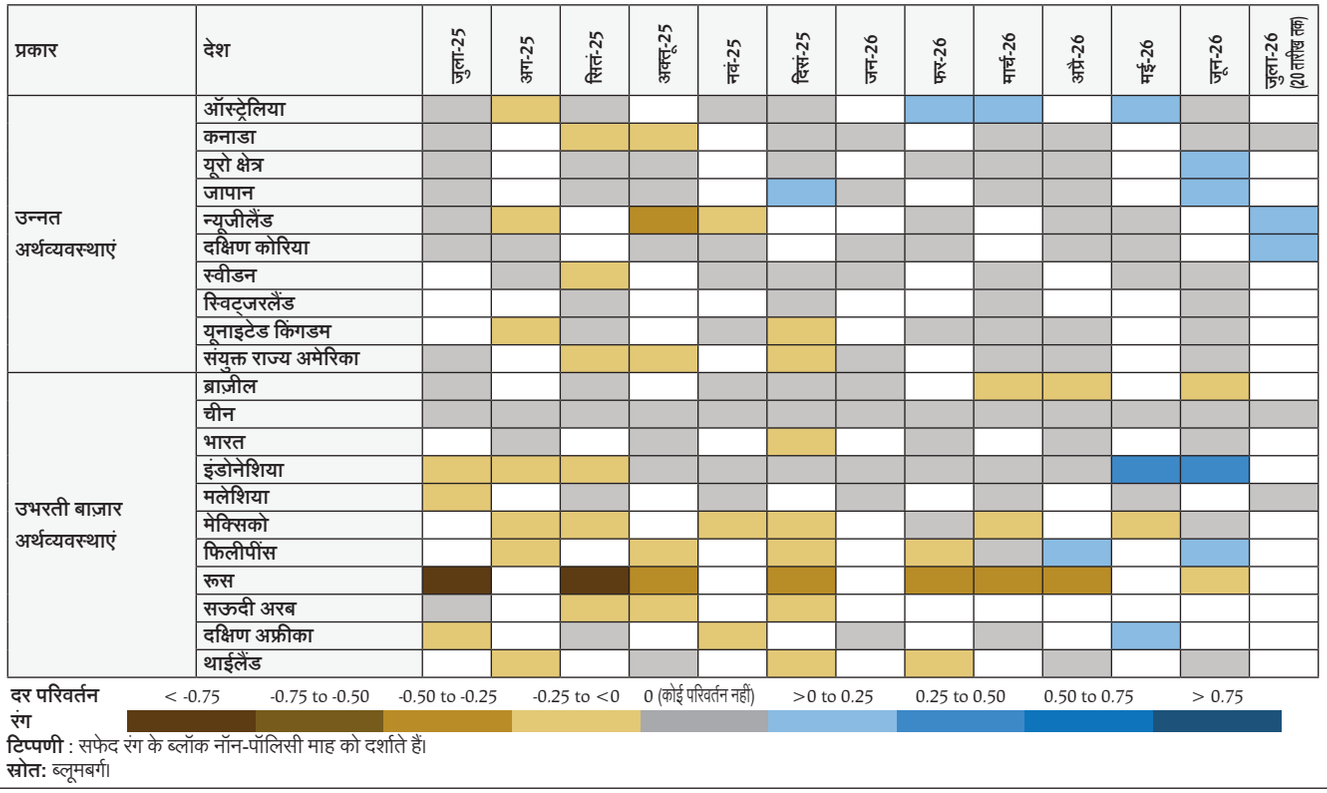
III. घरेलू गतिविधियां

जून के लिए उच्च-आवृत्ति संकेतक निरंतर आर्थिक गतिविधि का सुझाव देते हैं। औद्योगिक विकास मजबूत रहा, और सेवा क्षेत्र ने आघात-सहनीयता दिखाई।

कुल मांग

उच्च आवृत्ति संकेतकों ने जून में मजबूत आर्थिक गतिविधि को प्रतिबिंबित किया। ई-वे बिलों ने दोहरे अंकों की वृद्धि हासिल करना जारी रखा। माह के दौरान माल और सेवा कर (जीएसटी)

चार्ट II.9: बड़े केंद्रीय बैंकों की नीतिगत कार्रवाई में अंतर



टिप्पणी : सफेद रंग के ब्लॉक नॉन-पॉलिसी माह को दर्शाते हैं।
स्रोत: ब्लूमबर्ग।

राजस्व में वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से आयात से कर राजस्व में तेज वृद्धि से प्रेरित थी।[2] इस बीच, कीमतों में ऊपर की ओर संशोधन के बावजूद जून में पेट्रोल और डीजल की खपत में वृद्धि में मजबूती आई। हालांकि, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), बिटुमेन और नेफ्था की खपत में गिरावट के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की कुल खपत में धीमी गति से गिरावट जारी रही। गर्म परिस्थितियों और मानसून की देरी से शुरुआत के कारण आंशिक रूप से बिजली की मांग में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। अगस्त 2025[3] में फास्टैग वार्षिक पास योजना की शुरुआत के बाद टोल लेनदेन की मासिक संख्या में गिरावट जारी रही। डिजिटल भुगतान मूल्य ने तत्काल सकाल निपटान (आरटीजीएस) लेनदेन द्वारा संचालित स्थिर वृद्धि दर्ज की।[4] डिजिटल लेनदेन की मात्रा और मूल्य दोनों ने पिछले 19 महीनों में पहली बार 20 प्रतिशत से अधिक की मूल्य वृद्धि के साथ दोहरे अंकों की वृद्धि बनाए रखी (सारणी III.1)।

जून में ग्रामीण मांग में तेज वृद्धि से घरेलू मांग का समर्थन किया गया। खरीफ बुवाई गतिविधियों की शुरुआत के साथ ट्रैक्टर की बिक्री में तेजी आई, जबकि दोपहिया वाहनों की बिक्री में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई- मजबूत प्रवेश स्तर की मांग, आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्रमिक सामान्यीकरण और बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने[5] के आधार पर। शहरी मांग भी दृढ़ रही, यात्री वाहन की बिक्री को एसयूवी की निरंतर मांग, नए मॉडल लॉन्च और

[2] आयात से जीएसटी संग्रह में 34.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जबकि घरेलू जीएसटी राजस्व वृद्धि जून 2026 में 6.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) रही।

[3] वार्षिक पास उपयोगकर्ताओं को वर्ष में अधिकतम 200 यात्राएँ करने की अनुमति देता है, एक निश्चित शुल्क पर, जिससे प्रत्येक यात्रा पर टोल राजस्व में कमी आती है।

[4] जून में डिजिटल भुगतान मूल्य वृद्धि का नेतृत्व आरटीजीएस लेनदेन (72 प्रतिशत हिस्सेदारी) ने किया, जो 21 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ी।

[5] कुल दोपहिया बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का हिस्सा जून 2026 में 10.6 प्रतिशत तक बढ़ गया, जो एक साल पहले 7.3 प्रतिशत था, और पहली बार दो अंकों के आंकड़े को पार कर गया।

सारणी III.1: उत्साहवर्धक आर्थिक गतिविधि

संकेतक	जून-25	जुला-25	अग-25	सितं-25	अक्टू-25	नवं-25	दिसं-25	जन-26	फर-26	मार्च-26	अप्रै-26	मई-26	जून-26
जीएसटी ई-वे बिल (मात्रा)	19.3	25.8	22.4	21.0	8.2	27.6	23.5	15.8	18.8	12.9	11.8	10.9	14.5
जीएसटी राजस्व	6.5	8.2	6.9	10.0	7.6	0.7	6.1	6.2	8.1	8.8	8.7	3.2	13.9
टोल संग्रह (मात्रा)	15.5	14.8	12.7	4.5	4.6	2.9	0.4	-1.8	-8.7	-4.0	-5.8	-7.2	-6.3
बिजली मांग (मात्रा)	-2.3	2.6	3.8	3.5	-5.8	-0.6	5.8	3.8	1.0	0.8	3.0	10.8	11.5
पेट्रोलियम उत्पादों का कुल उपभोग (मात्रा)	0.5	-4.4	4.8	7.0	-1.5	0.6	4.5	0.3	4.5	3.2	-6.5	-5.3	-3.1
जिसमें शामिल हैं:													
पेट्रोल	6.8	5.9	5.5	8.0	7.4	2.6	7.1	6.1	6.1	7.6	6.8	3.4	7.5
डीजल	1.5	2.3	1.2	6.5	-0.3	4.8	5.2	3.3	4.3	8.1	0.8	1.6	6.2
एविएशन टरबाइन ईंधन	3.3	-2.3	-2.9	-0.8	2.1	5.4	0.2	5.5	4.0	0.6	-0.1	0.9	0.0
डिजिटल भुगतान – मात्रा	28.3	30.9	31.1	28.1	21.5	30.2	26.8	25.4	23.5	21	22.3	21.3	18.9
डिजिटल भुगतान – मूल्य	17.4	16.6	5.3	13.4	8.8	14.7	15.2	11.3	17.9	12.6	14.4	10.8	20.5

<<संकुचन ---------- विस्तार>>

टिप्पणियाँ: 1. सभी संकेतकों के लिए वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत) की गणना की गई है।
2. हीटमैप अप्रैल 2023 से उस नवीनतम माह तक के आंकड़ों पर लागू किया गया है, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं।
3. सकल जीएसटी राजस्व में तीन घटक शामिल हैं- आईजीएसटी, सीजीएसटी, और एसजीएसटी।
4. डिजिटल भुगतान के लिए, हीटमैप अप्रैल 2024 से उस नवीनतम माह तक के आंकड़ों पर लागू किया गया है, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं।
5. जून 2026 के लिए डिजिटल भुगतान के आंकड़े अनंतिम हैं।
6. हीटमैप प्रत्येक संकेतक के लिए आंकड़ों की सीमा को एक रंग ग्रेडिएंट योजना में अनुवाद करता है, जिसमें लाल रंग संबंधित आंकड़ा श्रृंखला के न्यूनतम मानों को और हरा रंग उच्चतम मानों को दर्शाता है।

स्रोत: माल एवं सेवा कर नेटवर्क; आरबीआई; केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण; भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम; और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय।

आकर्षक वित्तपोषण योजनाओं से लाभ हुआ। प्रमुख विमानन वाहकों द्वारा क्षमता युक्तिकरण और विमानन टरबाइन ईंधन की लागत में वृद्धि के बीच घरेलू हवाई यात्री यातायात में गिरावट आई (सारणी III.2)।

जून में, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति द्वारा मापी गई अखिल भारतीय बेरोजगारी दर, ग्रामीण बेरोजगारी दर में गिरावट के साथ स्थिर रही, जबकि शहरी बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई।[6] ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले महीने की तुलना में श्रम बल भागीदारी

सारणी III.2: उच्च आवृत्ती संकेतक- मज़बूत मांग की स्थिति

	संकेतक	जून-25	जुला-25	अग-25	सितं-25	अक्टू-25	नवं-25	दिसं-25	जन-26	फर-26	मार्च-26	अप्रै-26	मई-26	जून-26
शहरी मांग	घरेलू हवाई यात्री यातायात	3.7	-2.5	-0.5	-2.5	3.5	7.0	-4.9	3.1	-0.1	-1.3	-2.8	7.7	-1.0
	खुदरा यात्री वाहन बिक्री	2.5	-0.8	0.9	5.8	10.7	20.4	26.6	7.2	26.1	21.5	18.1	23.2	28.6
ग्रामीण मांग	खुदरा ऑटोमोबाइल बिक्री	4.8	-4.3	2.8	5.2	40.5	2.1	14.6	17.6	25.6	25.3	17.4	9.5	21.8
	जिसमें की ट्रैक्टर की बिक्री	8.7	11.0	30.1	3.6	14.2	56.5	15.8	22.9	36.4	10.9	28.7	11.2	25.3
	दोपहिया वाहनों की बिक्री	4.7	-6.5	2.2	6.5	51.8	-3.1	9.5	20.8	25.0	28.7	17.2	7.5	21.2

<<संकुचन ---------- विस्तार>>

टिप्पणियाँ: 1. सभी संकेतक के लिए मात्रा के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में) गणना की गई है।
2. हीटमैप अप्रैल 2023 से लेकर उस आखिरी महीने तक के डेटा पर लागू होता है जिसके लिए डेटा उपलब्ध है।
3. हीटमैप हर संकेतक के लिए डेटा रेंज को एक कलर ग्रेडिएंट स्कीम में बदलता है, जिसमें लाल रंग सबसे कम वैल्यू दिखाता है और हरा रंग संबंधित डेटा सीरीज़ की सबसे ज़्यादा वैल्यू दिखाता है।
4. जून 2026 के लिए घरेलू हवाई यात्री यातायात की वृद्धि दर का डेटा दैनिक डेटा को एकत्रित करके गणना की जाती है।
5. खुदरा ऑटोमोबाइल बिक्री के डेटा में दो पहिया, तीन पहिया, यात्री वाहन, ट्रैक्टर और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री शामिल है।

स्रोत: एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया; और फेडरेशन ऑफ़ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (एफ़एडीए)।

[6] पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे मासिक बुलेटिन, जून 2026।

दर और श्रमिक-जनसंख्या अनुपात भी अपरिवर्तित रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में उनमें मामूली वृद्धि हुई।[7] हालांकि जून में नए ऑर्डर में धीमी वृद्धि के कारण पीएमआई रोजगार संकेतक में कमी आई, लेकिन 'नौकरी जॉबस्पीक सूचकांक' से पता चलता है कि बीमा, एफ़एमसीजी और दूरसंचार क्षेत्र की मदद से व्हाइट-कॉलर हायरिंग में तेज़ी आई (सारणी III.3)।

रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए विकसित भारत-गारंटी (वीबी-जी आरएएम जी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के स्थान पर 01 जुलाई 2026 से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना, सार्वजनिक परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार करना और प्रौद्योगिकी-संचालित कार्यान्वयन शुरू करना है। वीबी-जी आरएएम जी 125 दिनों के वार्षिक रोजगार की गारंटी देता है, राज्यों को कृषि मौसम के दौरान कुल 60-दिन के ठहराव को अधिसूचित करने का अधिकार देता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस), और बायोमेट्रिक-आधारित निगरानी लाता है, और योजना का ध्यान केंद्र-निर्दिष्ट क्षेत्रों पर स्थानांतरित करता है।[8] इसने केंद्र द्वारा निर्धारित राज्य-वार मानक आवंटन के साथ प्रक्षेपण-आधारित निधि आवंटन को बदल दिया है। सरकार ने मनरेगा के तहत राष्ट्रीय औसत अधिसूचित मजदूरी को 298.8 रुपये प्रति दिन से संशोधित कर 327.4 रुपये प्रति दिन कर दिया है और देश भर में न्यूनतम राष्ट्रीय स्तर वेतन ₹300 प्रति दिन की शुरुआत की है।

सरकारी वित्त

केंद्र सरकार के प्रमुख घाटे के संकेतक, जैसे, सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी), राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा

सारणी III.3: रोज़गार के लिए उच्च आवृति संकेतकों में कमी

संकेतक	जून-25	जुला-25	अग-25	सितं-25	अक्टू-25	नवं-25	दिसं-25	जन-26	फर-26	मार्च-26	अप्रै-26	मई-26	जून-26
बेरोज़गारी दर (पीएलएफ़एस: अखिल भारतीय)	5.6	5.2	5.1	5.2	5.2	4.7	4.8	5.0	4.9	5.1	5.2	5.5	5.5
बेरोज़गारी दर (पीएलएफ़एस: ग्रामीण)	4.9	4.4	4.3	4.6	4.4	3.9	3.9	4.2	4.2	4.3	4.6	5.1	5.0
बेरोज़गारी दर (पीएलएफ़एस:शहरी)	7.1	7.2	6.7	6.8	7.0	6.5	6.7	7.0	6.6	6.8	6.6	6.4	6.6
नौकरी जॉबस्पीक सूचकांक	10.5	6.8	3.4	10.1	-9.3	23.5	13.2	3.4	11.9	9.2	5.8	1.0	6.1
पीएमआई रोज़गार: विनिर्माण	55.1	53.3	53.1	52.1	52.4	50.9	50.5	51.1	51.5	52.6	54.6	53.0	50.8
पीएमआई रोज़गार: सेवाएँ	55.1	51.4	52.2	51.9	51.4	51.6	49.8	50.8	51.6	52.7	53.4	53.2	50.3

<<संकुचन ---------- विस्तार>>

टिप्पणियाँ
1. सभी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) संकेतक वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में हैं और 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए हैं।
2. नौकरी सूचकांक के लिए वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में) की गणना की गई है।
3. हीटमैप अप्रैल 2023 से जून 2026 तक के डेटा पर लागू किया जाता है।
4. पीएलएफ़एस बेरोज़गारी दर के लिए हीटमैप अप्रैल 2025 से जून 2026 तक के डेटा पर लागू किया गया है।
5. हीटमैप हर संकेतक के लिए डेटा रेंज को एक कलर ग्रेडिएंट स्कीम में बदलता है, जिसमें लाल रंग सबसे कम वैल्यू दिखाता है और हरा रंग संबंधित डेटा सीरीज़ की सबसे ज़्यादा वैल्यू दिखाता है।
6. सभी पीएमआई वैल्यू सूचकांक के रूप में रिपोर्ट की जाती हैं। पीएमआई वैल्यू >50 का मतलब है बढ़ोतरी, <50 का मतलब है संकुचन और =50 का मतलब है 'कोई बदलाव नहीं'। पीएमआई हीटमैप में, लाल रंग सबसे कम वैल्यू दिखाता है, पीला रंग 50 (या कोई बदलाव नहीं वैल्यू) दिखाता है, और हरा रंग हर पीएमआई सीरीज़ में सबसे ज़्यादा वैल्यू दिखाता है।।
7. पीएलएफ़एस बेरोज़गारी दरें उल्टे पैमाने पर एन्कोड की गई हैं - सबसे कम को हरे रंग में और सबसे ज़्यादा को लाल रंग में चिह्नित किया गया है।

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार; इन्फो एज; और एस एंड पी ग्लोबल।

[7] कुल श्रम शक्ति भागीदारी दर और कार्यकर्ता-जनसंख्या अनुपात क्रमशः जून 2026 में 54.4 प्रतिशत और 51.4 प्रतिशत पर रहे, जो मई 2026 के समान स्तर है।

[8] "विकसित भारत-जी आरएएमजी अधिनियम 2025", प्रेस सूचना ब्यूरो, 22 दिसंबर, 2025।

[9] इसके अतिरिक्त, अधिनियम ने वेतन, सामग्री, और प्रशासनिक लागत को कवर करते हुए 60:40 (उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10) की एक समान केंद्र-राज्य वित्तपोषण पैटर्न को अपनाया।

[10] "वीबी-जी आरएएमजी अधिनियम, 2025 के अंतर्गत संशोधित वेतन दरों की सरकार ने अधिसूचना जारी की", प्रेस सूचना ब्यूरो, 30 जून, 2026।

ने अप्रैल-मई: 2026-27 में अलग-अलग पैटर्न प्रदर्शित किए। जबकि बजट अनुमानों (बीई) के प्रतिशत के रूप में जीएफडी पिछले वित्तीय वर्ष[11] की इसी अवधि की तुलना में अधिक था, राजस्व और प्राथमिक दोनों खातों में अधिशेष दर्ज किया गया, हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में कम था (चार्ट III.1ए)।

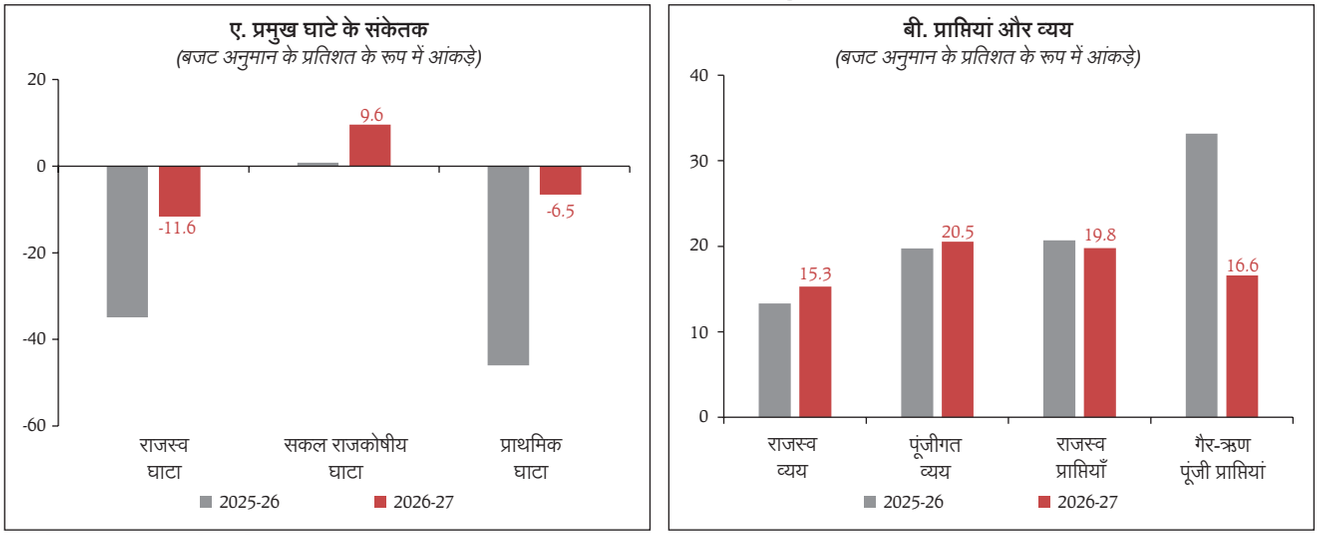
उच्च राजकोषीय घाटा राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों में विस्तार के साथ-साथ गैर-ऋण कुल प्राप्तियों में संकुचन से प्रेरित था।[12] राजस्व व्यय में वृद्धि प्रमुख सब्सिडी और ब्याज भुगतान पर उच्च व्यय के कारण थी।[13] इस बीच, पूंजीगत व्यय ने अपनी दोहरे अंकों की वृद्धि को बनाए रखा, जो सार्वजनिक निवेश पर सरकार के निरंतर ध्यान को दर्शाता है। इसके विपरीत, गैर-ऋण कुल प्राप्तियां कम गैर-कर राजस्व और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के कारण संकुचित हुईं (चार्ट III.1बी)।[14]

बजट अनुमानों के प्रतिशत के रूप में राज्य सरकारों के प्रमुख घाटे के संकेतक अप्रैल-मई: 2026-27 में पिछले वर्ष की तुलना में मुख्य रूप से उच्च राजस्व प्राप्तियों के कारण कम रहे (चार्ट III.2)। राजस्व प्राप्तियों के भीतर, राज्य जीएसटी संग्रह में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, साथ ही राज्य उत्पाद शुल्क, स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में वृद्धि हुई। व्यय पक्ष पर, राजस्व व्यय अधिक रहा, जबकि पूंजीगत व्यय संकुचित था।

व्यापार

2026-27 की पहली तिमाही में पिछले वर्ष की इसी तिमाही में संकुचन से पण्य वस्तु निर्यात में सुधार हुआ।[15]

चार्ट III.1: अप्रैल-मई 2026-27 के दौरान केंद्र के प्रमुख राजकोषीय संकेतक



टिप्पणी: ऋणात्मक घाटा अधिशेष दिखाता है।
स्रोत: लेखा महानियंत्रक; और केंद्रीय बजट दस्तावेज।

[11] यह नवीनतम डेटा भारत के लेखा महानियंत्रक (सीजीए) द्वारा जारी किए गए अनुसार है।

[12] अप्रैल-मई: 2026-27 के दौरान, राजस्व व्यय और पूंजी व्यय में क्रमशः 20.1 प्रतिशत और 13.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह वृद्धि क्रमशः 9.4 प्रतिशत और 54.1 प्रतिशत थी। गैर-कर्ज़ कुल प्राप्तियों में 2.0 प्रतिशत की कमी आई, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 28.0 प्रतिशत बढ़ी थी।

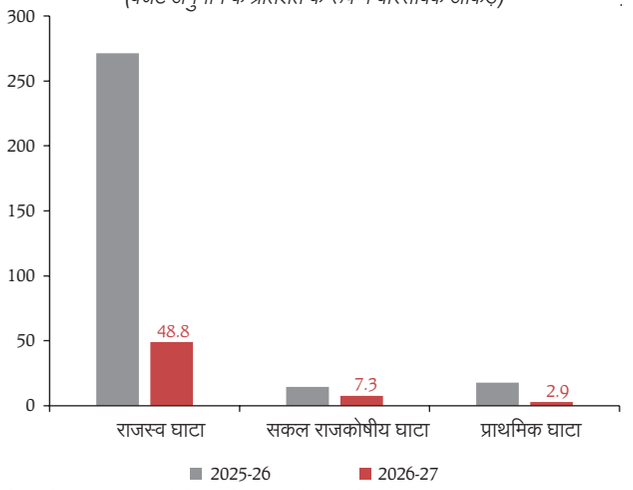
[13] अप्रैल-मई: 2026-27 के दौरान, प्रमुख सब्सिडी (भोजन, उर्वरक और पेट्रोलियम) और ब्याज भुगतान में क्रमशः 47.4 प्रतिशत और 22.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि में यह वृद्धि क्रमशः (-) 6.3 प्रतिशत और 19.4 प्रतिशत थी।

[14] अप्रैल-मई: 2026-27 के दौरान, गैर-कर राजस्व और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में क्रमशः (-)1.7 प्रतिशत और (-) 22.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि अप्रैल-मई: 2025-26 में यह क्रमशः 41.8 प्रतिशत और 1,108.9 प्रतिशत थी। गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों की वृद्धि अप्रैल-मई: 2025-26 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के मोनेटाइजेशन के कारण तेज हो गई थी।

[15] 2026-27 की पहली तिमाही के दौरान, निर्यात 129.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुँच गया और 15.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की, जबकि 2025-26 की पहली तिमाही में यह (-) 2.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) था (111.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर)। 30 प्रमुख वस्तुओं में से 19 के निर्यात में वृद्धि हुई, और शीर्ष 20 गंतव्यों में से 17 में वृद्धि दर्ज की गई।

चार्ट III.2: अप्रैल-मई 2026-27 के दौरान राज्यों के प्रमुख राजकोषीय संकेतक

(बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में वास्तविक आंकड़े)



टिप्पणी: डेटा 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।
स्रोत: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक।

आयात भी दहाई अंकों में बढ़ा।[16] हालांकि, पण्य वस्तु व्यापार घाटा 2026-27 की पहली तिमाही में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहा, जो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक सामानों, पेट्रोलियम उत्पादों और स्वर्ण के आयात में तेजी से वृद्धि से प्रेरित रहा।[17]

जून 2026 के माध्यम से, निर्यात और आयात दोनों ने लगातार तीसरे महीने मजबूत वृद्धि दर्ज की।[18] निर्यात वृद्धि इंजीनियरिंग वस्तुओं जैसे उत्पादों द्वारा संचालित थी; इलेक्ट्रॉनिक सामान; और रत्न और आभूषण।[19,20] हालाँकि, युद्ध की शुरुआत के बाद से पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात सबसे कम रहा।[21] आयात की वृद्धि का नेतृत्व पेट्रोलियम, कच्चा तेल और संबंधित उत्पादों इलेक्ट्रॉनिक सामान; और उर्वरक जैसी वस्तुओं द्वारा किया गया।[22] ओमान, ब्राज़ील और नाइजीरिया जैसे देशों से आयात में बहुत अधिक वृद्धि (तीन अंक) हुई है, जो पेट्रोलियम, कच्चे तेल और उत्पादों के आयात के स्रोत में विविधता लाने के लिए भारत की हालिया पहलों को दर्शाती है।[23] स्वर्ण के आयात द्वारा, हालांकि 12 महीने के निचले स्तर पर, जून में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि चांदी का आयात गिर गया।[24]

जून 2026 में पण्य वस्तु व्यापार घाटा पांच महीने के उच्च स्तर तक बढ़ गया, और वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर भी बढ़ा (चार्ट III.3)।[25] उच्च व्यापार घाटा तेल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों द्वारा संचालित था, इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के कारण घाटा पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुना हो गया।[26].

भारत के व्यापार विविधीकरण प्रयासों के हिस्से के रूप में, भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) 15 जुलाई, 2026 से लागू हुआ। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को पहले दिन से ही यूके के बाजार में लगभग सार्वभौमिक शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान करता है, जबकि भारत का व्यापार उदारीकरण धीमा और चयनात्मक है, जो एक दशक में फैला हुआ है, जिसमें कृषि बड़े पैमाने पर संरक्षित है और ऑटोमोबाइल कुछ प्रतिबंधों के अधीन हैं।

[16] 2026-27 की पहली तिमाही के दौरान, 216.2 अरब अमेरिकी डॉलर के आयात में 19.9 प्रतिशत (वार्षिक आधार पर) की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष के 180.3 अरब अमेरिकी डॉलर थी और 2025-26 की चौथी तिमाही के 194.5 अरब अमेरिकी डॉलर से 11.1 प्रतिशत (तिमाही आधारित) की वृद्धि हुई। 30 वस्त्रों में से 21 का आयात बढ़ा, और शीर्ष 20 देशों में से 18 से आयात में वृद्धि हुई।

[17] भारत का व्यापारिक घाटा 2026-27 की पहली तिमाही के दौरान 86.9 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो एक वर्ष पहले के 68.7 अरब अमेरिकी डॉलर और 2025-26 की चौथी तिमाही के 82.5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है।

[18] जून 2026 में वस्त्र निर्यात 15.5 प्रतिशत (वार्षिक आधार पर) बढ़कर US$ 40.4 अरब हो गया, जो जून 2025 में US$ 35.0 अरब था। वस्त्र आयात 31.0 प्रतिशत (वार्षिक आधार पर) बढ़कर जून 2026 में US$ 70.8 अरब हो गया, जो जून 2025 में US$ 54.1 अरब था।

[19] जून 2026 में, 30 वस्तुओं में से 19 ने निर्यात वृद्धि में योगदान दिया, जिसमें इंजीनियरिंग वस्तुओं में 20.7 प्रतिशत (वार्षिक आधार पर) की वृद्धि, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में 18.9 प्रतिशत और रत्न और आभूषणों में 34.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सभी प्रकार के रेडीमेड गारमेंट्स, चमड़ा और चमड़े के उत्पाद, सिरेमिक उत्पाद और कांच के बर्तनों जैसे खंडों में निर्यात में गिरावट आई।

[20] प्रमुख 20 गंतव्यों में से 17 में निर्यात बढ़ा। यूएई, सिंगापुर, चीन, नीदरलैंड्स और यूके जैसे शीर्ष गंतव्यों में निर्यात बढ़ा, जबकि अमेरिका में मामूली कमी आई।

[21] पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात जून 2026 में 4.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा (युद्ध की शुरुआत के बाद सबसे कम), जो साल-दर-साल 9.2 प्रतिशत बढ़ा। मार्च, अप्रैल और मई में पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात क्रमशः 5.2 बिलियन, 9.7 बिलियन और 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

[22] जून 2026 में, 30 प्रमुख वस्तुओं में से 25 ने आयात वृद्धि में सकारात्मक योगदान दिया। कच्चा तेल और उत्पादों का आयात 40.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक सामान 58.8 प्रतिशत बढ़ा, और उर्वरकों का आयात 201.3 प्रतिशत बढ़ा।

[23] कुल मिलाकर, जून 2026 में शीर्ष 20 देशों में से 18 से आयात बढ़ा, जिसमें ओमान, ब्राज़ील और नाइजीरिया से आयात क्रमशः 135.6 प्रतिशत, 162.3 प्रतिशत, और 301.9 प्रतिशत बढ़ा।

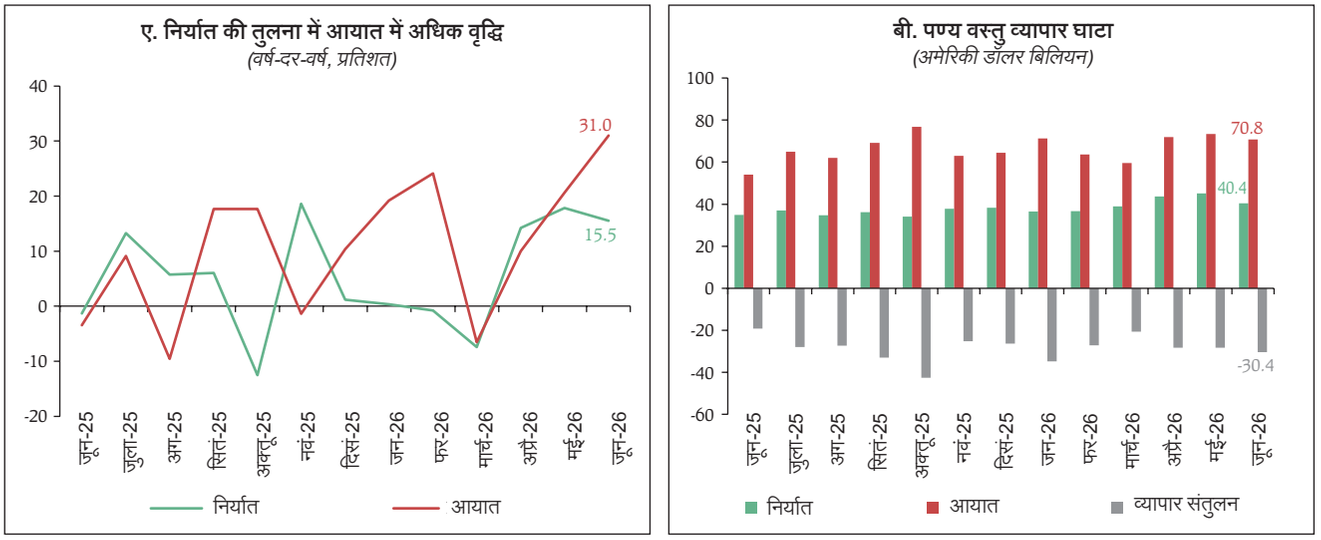
[24] मूल्य के दृष्टिकोण से, जून 2026 में सोने का आयात 2.0 अरब अमेरिकी डॉलर पर 7.1 प्रतिशत (साल-दर-साल) बढ़ा, जबकि चांदी का आयात 73.6 प्रतिशत (साल-दर-साल) घट गया।

[25] भारत का वस्तु व्यापार घाटा जून 2026 में 30.4 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष 19.1 अरब अमेरिकी डॉलर और मई 2026 में 28.3 अरब अमेरिकी डॉलर था।

[26] तेल का घाटा जून 2026 में 14.5 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो जून 2025 में 9.3 अरब अमेरिकी डॉलर था, जबकि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का घाटा 4.3 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 8.4 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया।

चार्ट III.3: जून में भारत का पण्य वस्तु व्यापार घाटा

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

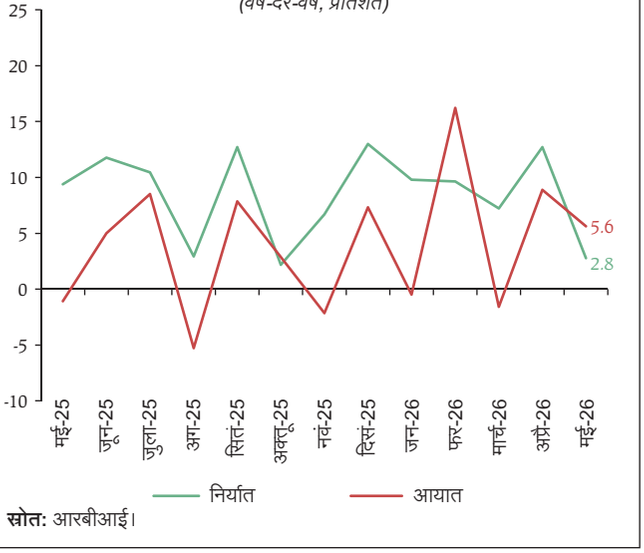


स्रोत: डीजीसीआई; और पीआईबी।

मई 2026 में, निर्यात की तुलना में तेज गति से आयात बढ़ने के साथ निवल सेवाओं के निर्यात में मामूली गिरावट आई (चार्ट III.4)।[27] मई 2026 में सेवा निर्यात में वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से व्यापार और परिवहन सेवाओं द्वारा संचालित थी, जबकि सॉफ्टवेयर, परिवहन और व्यावसायिक सेवाओं में वृद्धि के माध्यम से आयात में तेज दर से वृद्धि हुई।[28]

चार्ट III.4: मई में निवल सेवा निर्यात में मामूली गिरावट

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)



स्रोत: आरबीआई।

कुल आपूर्ति

कृषि

संचयी दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्षा (20 जुलाई तक) विषम अस्थायी और स्थानिक वितरण के साथ सामान्य से कम रहा (चार्ट III.5.ए)। परिणामस्वरूप, जलाशय का भंडारण दशकीय औसत से कम रहा, लेकिन, 2023 के पिछले अल नीनो वर्ष से अधिक है (चार्ट III.5.बी)। चालू खरीफ मौसम के दौरान, पिछले वर्ष के साथ रकबे में अंतर कम हो रहा है (चार्ट III.5.सी)।[29] भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने जुलाई के लिए सामान्य से कम वर्षा का अनुमान लगाया है।

[27] मई 2026 में निवल सेवा निर्यात 0.3 प्रतिशत (साल-दर-साल) घटकर 15.7 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। अप्रैल - मई 2026 के दौरान, निवल सेवा निर्यात 31.7 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 34.3 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया।

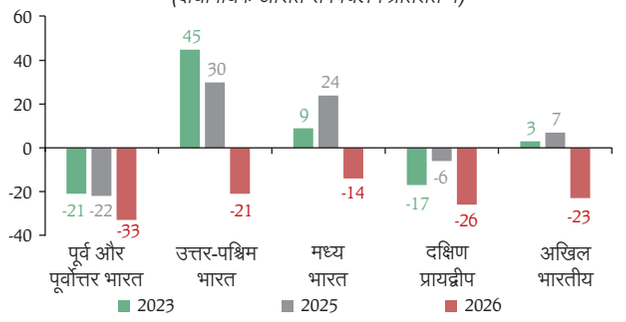
[28] मई 2026 में सेवा निर्यात में 2.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जबकि मई 2025 में यह 9.4 प्रतिशत थी, वहीं सेवा आयात में मई 2026 में 5.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जबकि मई 2025 में यह 1.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी।

[29] 17 जुलाई तक खरीफ की बुवाई का क्षेत्रफल पूरी मौसम की सामान्य क्षेत्रफल का 59.6 प्रतिशत था। पिछले वर्ष की तुलना में, बुवाई क्षेत्रफल में अंतर घटकर 6.0 प्रतिशत रह गया, जो पिछले सप्ताह (10 जुलाई 2026) में 16.0 प्रतिशत था।

चार्ट III. 5: कृषि उत्पादन में गिरावट के जोखिम

ए. अब तक मॉनसून में बारिश कम होना

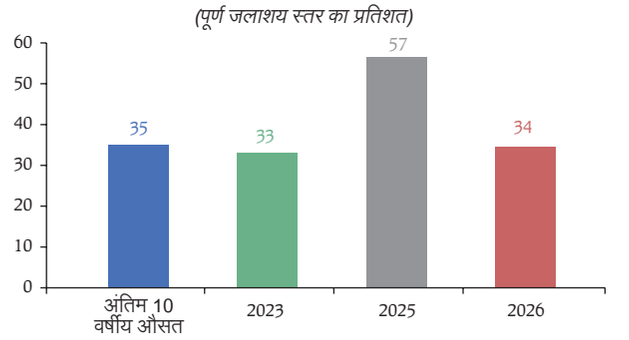
(दीर्घावधिक औसत से विचलन प्रतिशत में)



टिप्पणी: बारिश का डेटा 01 जून से 20 जुलाई तक है।
स्रोत: भारत मौसम विज्ञान विभाग।

बी. जलाशय स्तर

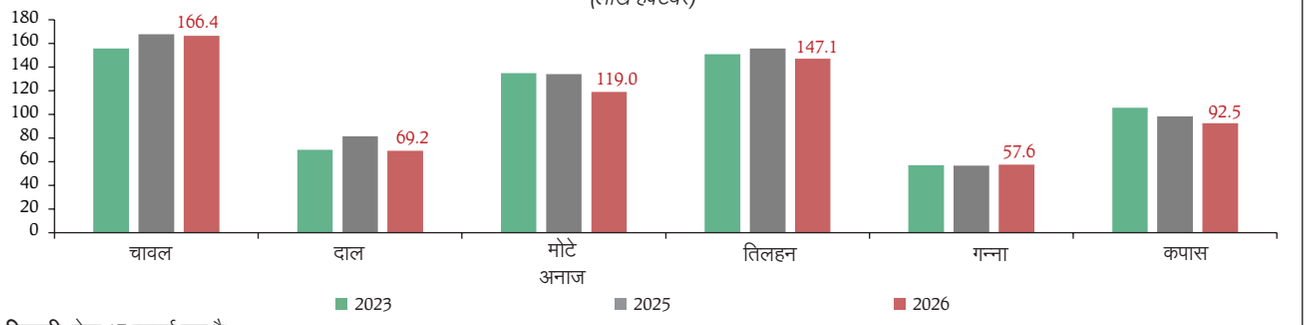
(पूर्ण जलाशय स्तर का प्रतिशत)



टिप्पणी: जलाशयों का डेटा 16 जुलाई तक का है।
स्रोत: केंद्रीय जल आयोग।

सी. खरीफ बुवाई में प्रगति

(लाख हेक्टेयर)

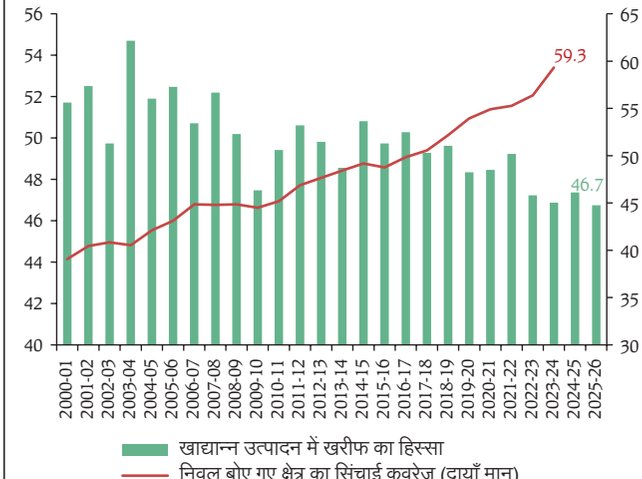


टिप्पणी: डेटा 17 जुलाई तक है।
स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएफ़डबल्यू)।

जबकि कृषि क्षेत्र के लिए मानसून का प्रदर्शन महत्वपूर्ण बना हुआ है, सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि और खरीफ फसलों की घटती हिस्सेदारी के कारण दक्षिण-पश्चिम मानसून पर कृषि की निर्भरता धीरे-धीरे कम हो रही है - जो रबी फसलों की तुलना में मानसून पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर हैं - कुल खाद्यान्न उत्पादन में (चार्ट III.6)। इसके अलावा, वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड उत्पादन के बाद गेहूं और चावल की मजबूत खरीद[30] के परिणामस्वरूप सार्वजनिक खाद्यान्न का भंडार पर्याप्त बना हुआ है।[31]

चार्ट III.6: भारतीय कृषि में सिंचाई कवरेज में सुधार

(प्रतिशत)



टिप्पणी: वर्ष 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का डेटा तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार है।
स्रोत: एमओएएफ़डबल्यू: एमओएसपीआई और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी।

[30] रबी विपणन मौसम (आरएमएस) 2026-27 (अप्रैल-मार्च) के दौरान गेहूं की खरीद, 30 जून, 2026 तक, 357.6 लाख टन रही, जो सरकार के खरीद लक्ष्य 355.4 लाख टन को पार कर गई है। यह आरएमएस 2025-26 के दौरान की खरीद से 19.4 प्रतिशत अधिक है। खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2025-26 (अक्टूबर-सितंबर) के दौरान चावल की खरीद, 20 जुलाई, 2026 तक, 562 लाख टन रही, जो केएमएस 2024-25 की समान अवधि की तुलना में 5.5 प्रतिशत अधिक है।

[31] 01 जुलाई, 2026 को चावल और गेहूं का स्टॉक क्रमशः 4.9 और 1.9 गुना त्रैमासिक भंडार मानकों के बराबर था।

औद्योगिक गतिविधि के मासिक संकेतक

उच्च आवृत्ति संकेतकों के आधार पर, पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद औद्योगिक गतिविधि मजबूत रही। मई में, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि मजबूत विनिर्माण गतिविधि और विद्युत उत्पादन के कारण हुई। जून में, विनिर्माण पीएमआई कुछ कमी के बावजूद विस्तारवादी क्षेत्र में रहा। पिछले वर्ष की तुलना में जून में ऑटोमोबाइल उत्पादन में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जिससे जीएसटी दरों में कमी आई। बिजली उत्पादन में भी वृद्धि हुई क्योंकि देश ने लंबे समय तक हीटवेव की स्थिति का अनुभव किया (सारणी III.4)। पूंजीगत वस्तुओं के आयात में जून 2021 के बाद से सबसे अधिक वृद्धि देखी गई, जो इलेक्ट्रॉनिक सामानों द्वारा संचालित है। कोर उद्योग सूचकांक (आईसीआई) [आधार वर्ष 2022-23 के साथ संशोधित श्रृंखला और लौह अयस्क 9वें उद्योग के रूप में शामिल] जून 2026 में बिजली और लौह अयस्क के कारण 5 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया।

सेवा गतिविधि के मासिक संकेतक

जून में सेवा क्षेत्र आघात-सहनीय रहा। जबकि सेवा पीएमआई में पिछले माह की तुलना में गिरावट आई, यह नए

सारणी III.4: मजबूत बने रहने वाले उद्योगों के उच्च आवृति संकेतक

सूचक	जून-25	जुला-25	अग-25	सित-25	अक्टू-25	नवं-25	दिसं-25	जन-26	फर-26	मार्च-26	अप्रै-26	मई-26	जून-26
आईआईपी हेडलाइन	2.2	5.4	4.7	6.1	-0.9	7.0	6.7	4.1	4.4	3.0	4.9	5.1	
आईआईपी विनिर्माण	2.4	5.1	3.6	5.5	-0.7	8.8	7.7	4.6	5.7	4.0	6.1	5.5	
आईआईपी पूंजीगत वस्तुएं	3.4	5.9	6.0	13.2	5.4	16.6	12.9	12.4	16.5	8.5	12.0	12.9	
पीएमआई विनिर्माण	58.4	59.1	59.3	57.7	59.2	56.6	55.0	55.4	56.9	53.9	54.7	55.0	54.2
पीएमआई निर्यात आदेश	60.6	57.3	56.1	56.5	54.7	54.1	54.0	54.1	53.2	55.0	56.3	53.7	52.1
पीएमआई विनिर्माण : भविष्य का आउटपुट	62.2	57.6	60.5	64.8	62.3	57.1	56.9	56.4	57.9	67.3	65.5	64.1	56.8
आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक	1.1	3.2	6.2	3.1	0.8	3.5	5.6	5.2	3.2	2.9	2.7	3.2	5.0
बिजली उत्पादन: पारंपरिक (मात्रा)	-6.1	-0.8	1.0	0.8	-10.6	-5.0	4.4	2.2	-1.5	-1.1	2.3	7.4	8.2
बिजली उत्पादन: नवीकरणीय (मात्रा)	28.7	26.4	22.7	16.4	21.4	22.9	18.0	22.9	25.3	11.7	23.2	29.9	
ऑटोमोबाइल उत्पादन (मात्रा)	1.2	10.7	8.1	10.8	-2.8	22.3	37.1	15.0	22.1	20.2	26.0	13.3	27.4
जिसमें - यात्री वाहन	-1.8	0.1	-4.1	16.1	9.8	22.8	23.1	5.6	9.8	9.0	12.8	10.9	17.6
दोपहिया वाहनों	1.4	12.3	10.0	9.8	-5.6	20.9	39.9	16.1	24.4	22.0	28.1	12.9	28.3
तिपहिया वाहनों	8.6	24.0	15.8	15.9	15.9	55.4	39.6	33.2	29.9	34.0	41.6	32.9	42.8
ट्रैक्टर	9.8	11.5	9.4	23.0	13.0	37.5	57.9	14.6	80.0	28.6	18.1	15.5	10.2
कच्चे इस्पात का उत्पादन (मात्रा)	12.6	13.8	12.8	13.7	8.9	11.1	10.8	11.5	11.4	10.6	4.5	1.9	
तैयार स्टील उत्पादन (मात्रा)	10.9	13.8	13.8	14.0	7.2	12.4	10.9	12.5	8.6	8.2	6.3	6.8	
पूंजीगत वस्तुओं का आयात (मूल्य)	3.4	13.5	0.2	12.8	12.0	14.8	17.9	5.2	17.0	11.7	21.6	18.0	38.7

<<संकुचन ---------- विस्तार>>

टिप्पणियाँ : 1. वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में) सभी संकेतकों (पीएमआई को छोड़कर) के लिए गणना की गई है।

2. हीटमैप हर संकेतक के लिए डेटा रेंज को एक कलर ग्रेडिएंट स्कीम में बदलता है, जिसमें लाल रंग सबसे कम मान दिखाता है और हरा रंग संबंधित डेटा सीरीज़ की सबसे अधिक मान दिखाता है।

3. हीटमैप अप्रैल 2023 से लेकर उस आखिरी महीने तक के डेटा पर लागू होता है जिसके लिए डेटा उपलब्ध है।

4. सभी पीएमआई मान सूचकांक के रूप में रिपोर्ट की जाती हैं। पीएमआई मान 50 का अर्थ है बढ़ोतरी, <50 का अर्थ है कमी और 50 का अर्थ है 'कोई बदलाव नहीं'। पीएमआई हीटमैप में, लाल रंग सबसे कम मान दिखाता है, पीला रंग 50 (या कोई बदलाव नहीं) दिखाता है, और हरा रंग हर पीएमआई श्रेणी में सबसे अधिक मान दिखाता है।

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; एस&पी ग्लोबल; केंद्रीय बिजली प्राधिकरण। ऊर्जा मंत्रालय; भारतीय ऑटोमोबाइल विनिर्माता सोसाइटी: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, भारत सरकार: संयुक्त संयंत्र समिति: वाणिज्यिक खुफिया एवं सांख्यिकी महानिदेशालय; और ट्रैक्टर एवं यंत्रीकरण संघ।

निर्यात आदेशों के नेतृत्व में विस्तार क्षेत्र में मजबूती से बना रहा। घरेलू रसद संचालन ने भी स्थिर वृद्धि दिखाई, जैसा कि रेलवे माल यातायात में सुधार से परिलक्षित होता है। सड़क परिवहन क्षेत्र में, खुदरा वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में हल्के और मध्यम खंडों द्वारा मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी ओर, उड़ान व्यवधानों, हवाई क्षेत्र के बंद होने, रीरूटिंग और ईंधन की लागत में वृद्धि के कारण अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात में कमी जारी रही, हालांकि गिरावट की गति कम हो गई। मई में इस्पात की खपत मजबूत हुई, जो बुनियादी ढांचे और निर्माण क्षेत्रों की निरंतर मांग को दर्शाती है। मई में बंदरगाह कार्गो यातायात की वृद्धि में तेजी आई (सारणी III.5)।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने परीक्षण के आधार पर 14 जुलाई 2026 को सेवा उत्पादन सूचकांक (आईएसपी) [आधार वर्ष: 2024-25] जारी किया। यह औपचारिक सेवा क्षेत्र की गतिविधि का मासिक उपाय प्रदान करके भारत की सांख्यिकीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण अंतर को भरता है, जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का पूरक है। इसे जीएसटी डेटा और क्षेत्र-विशिष्ट प्रशासनिक रिकॉर्ड का उपयोग करके संकलित किया गया है। आईएसपी 19 सेवा उप-क्षेत्रों को कवर करता है, जो सेवा क्षेत्र का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा है।[33] अप्रैल 2026 में, 19 में से 14 क्षेत्रों ने आवास और भोजन और खुदरा व्यापार के नेतृत्व में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की (चार्ट III.7)।

सारणी III.5: सेवाओं के लिए उच्च आवृति संकेतक मज़बूत बने रहे

संकेतक	जून-25	जुला-25	अग-25	सित-25	अक्टू-25	नवं-25	दिसं-25	जन-26	फर-26	मार्च-26	अप्रै-26	मई-26	जून-26
पीएमआई सेवाएँ	60.4	60.5	62.9	60.9	58.9	59.8	58.0	58.5	58.1	57.5	58.8	59.8	57.4
अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात	3.4	5.5	7.7	7.3	9.7	7.5	6.0	7.1	3.0	-18.5	-16.1	-9.1	-5.2
घरेलू हवाई कार्गो	2.6	4.8	7.1	2.8	-2.3	20.5	4.3	8.7	18.5	10.8	8.2	10.7	
अंतर्राष्ट्रीय हवाई कार्गो	-1.2	4.2	4.5	2.3	-2.3	12.7	12.6	8.4	17.5	-6.0	11.5	10.4	
बंदरगाह माल यातायात	5.6	4.0	2.5	11.5	11.9	14.5	12.7	7.6	5.1	0.6	2.4	6.6	
रेलवे माल यातायात: मालभाड़ा की उत्पत्ति	0.9	0.0	8.5	3.9	2.3	4.2	3.2	2.9	4.0	3.1	-1.0	1.4	4.0
खुदरा वाणिज्यिक वाहन बिक्री	6.6	0.2	8.6	2.7	21.1	17.0	24.6	15.1	28.9	15.1	18.8	5.3	16.9
इस्पात की खपत	9.2	7.3	10.0	8.9	2.4	6.0	5.4	4.9	12.8	13.7	8.1	9.4	
सीमेंट उत्पादन	8.2	11.6	5.4	5.0	5.2	14.6	13.7	11.3	8.9	4.7	8.2	8.4	
विदेशी पर्यटकों का आगमन	-24.2	-16.4	-5.1	-9.8	-5.1	-2.0	2.0	5.2	6.1	-1.6	-14.7		
होटल में रहने वालों की संख्या	-0.3	-2.4	-3.2	-0.6	0.0	3.8	-1.5	-8.5	1.2	-4.0	-1.0	9.9	

<<संकुचन ---------- विस्तार>>

टिप्पणियाँ : 1. वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में) सभी संकेतक (पीएमआई को छोड़कर) के लिए संगणित की गई है।
2. हीटमैप प्रत्येक संकेतक के लिए डेटा रेंज को एक रंग ग्रेडिएंट स्कीम में बदलता है, जिसमें लाल रंग सबसे कम मान दिखाता है और हरा रंग संबंधित डेटा श्रेणी का सर्वाधिक मान दिखाता है।
3. हीटमैप अप्रैल 2023 से लेकर उस आखिरी महीने तक के डेटा पर लागू होता है जिसके लिए डेटा उपलब्ध है।
4. सभी पीएमआई मान संकेतक के रूप में रिपोर्ट की जाती हैं। पीएमआई मान >50 का अर्थ है बढ़ोतरी, <50 का अर्थ है संकुचन और =50 का अर्थ है 'कोई परिवर्तन नहीं'। पीएमआई हीटमैप में, लाल रंग सबसे कम मान दिखाता है, पीला रंग 50 (या कोई परिवर्तन नहीं मान) दिखाता है, और हरा रंग प्रत्येक पीएमआई श्रेणी में सर्वाधिक मान दिखाता है।

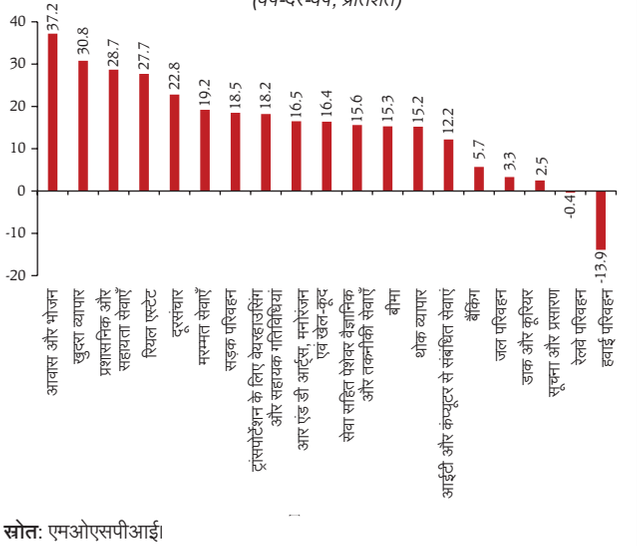
स्रोत: एफ़एडीए; इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन: रेल मंत्रालय: एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया: जॉइंट प्लांट कमिटी, इस्पात मंत्रालय: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय: पर्यटन मंत्रालय; एचवीएस एनारॉक; और एस एंड पी वैश्विक।

[32] मासिक डेटा हर महीने लगभग 60 दिनों की देरी के साथ जारी किया जाएगा।

[33] जब एनेवल सर्वे ऑफ इंकॉरपोरेटेड सर्विसेज सेक्टर एंटरप्राइजेस (एएसआईएसएसई) से डेटा उपलब्ध हो जाएगा, तब स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं के क्षेत्र को शामिल किया जाएगा।.

चार्ट III. 7: अप्रैल 2026 के लिए प्रमुख क्षेत्रों के सेवा उत्पादन का सूचकांक

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)



स्रोत: एमओएसपीआई।

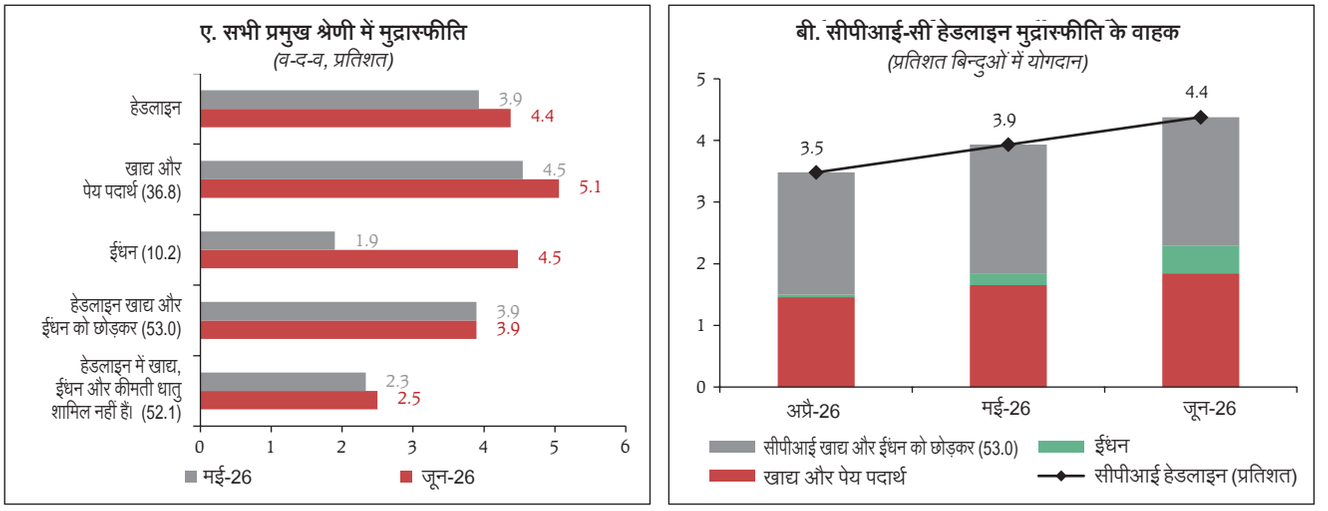
मुद्रास्फीति

हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति[34] ने जनवरी 2025 के बाद पहली बार लक्ष्य को पार किया, जो मई में 3.9 प्रतिशत से बढ़कर जून 2026 में 18 महीने के उच्च स्तर 4.4 प्रतिशत पर पहुंच गया। मुद्रास्फीति में वृद्धि 'खाद्य और पेय पदार्थों' और 'ईंधन' घटकों द्वारा संचालित थी, जबकि मुख्य मुद्रास्फीति अपरिवर्तित रही (चार्ट III.8)।[35] 12 में से आठ भागों[36] में जून में मुद्रास्फीति में क्रमिक वृद्धि देखी गई (चार्ट III.9)।

'खाद्य और पेय पदार्थों' की मुद्रास्फीति में वृद्धि मांस, खाद्य तेलों, फलों और मसालों द्वारा व्यापक आधार पर बनी रही।[37] माह-दर-माह (म-द-म) आधार पर भी सीपीआई बास्केट में 'खाद्य और पेय पदार्थों' के सभी उप-घटकों में जून में वृद्धि हुई। पेट्रोल, डीजल और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की खुदरा कीमतों में वृद्धि से प्रेरित जून,[38] में ईंधन मुद्रास्फीति बढ़ गई।[39]

जून 2026 में मुख्य मुद्रास्फीति 3.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) पर स्थिर रही, 'व्यक्तिगत देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और विविध वस्तुओं और सेवाओं' में गिरावट के बीच; 'रेस्तरां और

चार्ट III.8: जून में हेडलाइन मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी



टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त (सीपीआई-सी) (2024=100) में भार दर्शाते हैं।
2. कीमती धातुओं में 'सोने/हीरे/प्लैटिनम के गहने' और 'चांदी की गहने' शामिल हैं।

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ)।

[34] जैसा कि नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस (एनएसओ) द्वारा 13 जुलाई, 2026 को जारी अस्थायी आंकड़ों में बताया गया है।

[35] माह-दर-माह आधार पर, सीपीआई में 105 बेसिस पॉइंट्स (bps) की सकारात्मक गति आंशिक रूप से 60 bps के अनुकूल आधार प्रभाव से संतुलित हुई। सीपीआई के सभी प्रमुख घटक, अर्थात्, भोजन और पेय, ईंधन, और कोर (भोजन और ईंधन को छोड़कर) ने जून में सकारात्मक गति दर्ज की।

[36] सीपीआई-सी की टोकरी में 12 विभाग शामिल हैं, जिन्हें 43 समूहों में, फिर 92 वर्गों और 162 उप-वर्गों में विभाजित किया गया है।

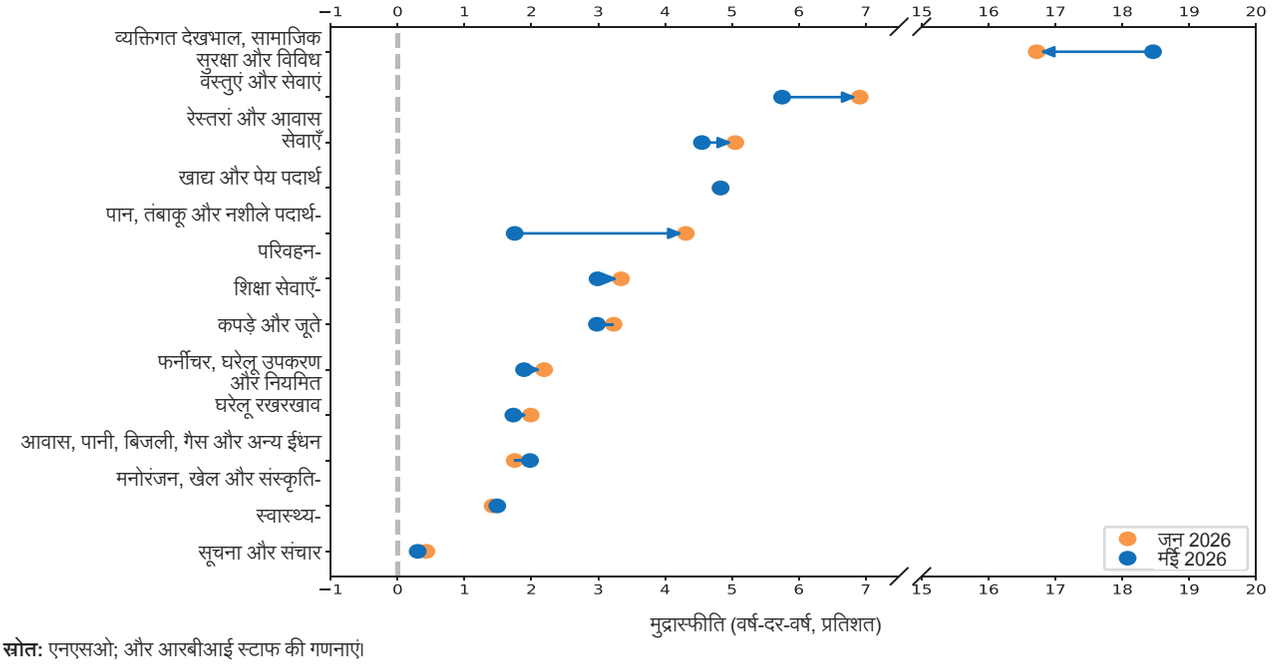
[37] मांस, खाने योग्य तेल, फल और मसालों में मुद्रास्फीति 8 प्रतिशत से अधिक थी।

[38] जून 2026 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) ईंधन मुद्रास्फीति मई 2026 में 1.9 प्रतिशत से बढ़कर 4.5 प्रतिशत हो गई।

[39] जून 2026 में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुद्रास्फीति क्रमशः 7.5 प्रतिशत और 8.4 प्रतिशत हो गई, जबकि मई 2026 में ये 3.1 प्रतिशत और 3.4 प्रतिशत थी, जो पेट्रोल और डीजल में खुदरा मूल्य वृद्धि के प्रभाव को दर्शाती है। इसी अवधि में एलपीजी की मुद्रास्फीति 2.2 प्रतिशत से बढ़कर 4.6 प्रतिशत हो गई।

चार्ट III.9: मुद्रास्फीति दर में भाग-वार बदलाव

(व-द-व, प्रतिशत)



स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ की गणनाएं।

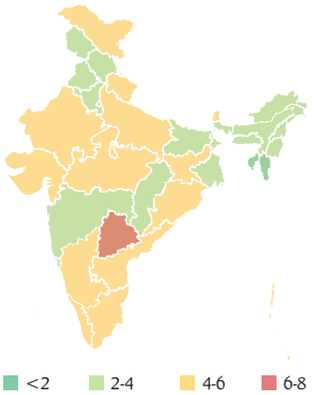
आवास सेवाओं' में वृद्धि से आंशिक रूप से संतुलित। कीमती धातु की कीमतें म-द-म के आधार पर गिर गईं, लेकिन वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति में वृद्धि जारी रही। कीमती धातुओं को छोड़कर, मुख्य मुद्रास्फीति, जून में 2.5 प्रतिशत पर रही, यह दर्शाता है कि अंतर्निहित मूल्य दबाव व्यापक रूप से नियंत्रित बना हुआ है।

शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई[40] और अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने मुद्रास्फीति 2-6 प्रतिशत की सीमा में दर्ज की (चार्ट III.10)[41]

प्रमुख खाद्य पदार्थों में अनुक्रमिक वृद्धि जुलाई में अब तक (20 जुलाई तक) व्यापक रूप से दिखाई दी। खाद्यानों में, प्रमुख खाद्य (चावल और गेहूं) की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई, जबकि दालों की कीमतों में वृद्धि की गति क्रमिक रूप से कम रही, मूंग दाल में म-द-म में मामूली गिरावट दर्ज की गई। जैव ईंधन उत्पादन के लिए खाद्य तेलों के उपयोग के बीच खाद्य तेल की कीमतों में व्यापक आधार पर वृद्धि देखी गई।[42] खराब होने वाली वस्तुओं के भीतर, प्रमुख सब्जियों, जैसे आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में जुलाई में और वृद्धि हुई, जिसमें प्याज में सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.11)।

चार्ट III.10: मुद्रास्फीति का स्थानिक वितरण: जून 2026

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)



मुद्रास्फीति सीमा	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या
<2	2
2-4	16
4-6	17
6-8	1

मासिक मुद्रास्फीति प्रवृत्ति	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या
गिरावट या स्थिर	5
बढ़ोतरी	31

टिप्पणियाँ: 1. मैप सिर्फ़ उदाहरण के लिए है।
2. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में क्रमशः 4.4 प्रतिशत और 3.6 प्रतिशत की मुद्रास्फीति देखी गई।

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ की गणनाएं।

[40] जून 2026 में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति क्रमशः 3.9 प्रतिशत और 4.7 प्रतिशत थी। मई 2026 के लिए संबंधित आंकड़े क्रमशः 3.5 प्रतिशत और 4.3 प्रतिशत थे।

[41] मुद्रास्फीति राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1.6 प्रतिशत से 6.4 प्रतिशत तक रही। तेलंगाना में मुद्रास्फीति लगातार 6 प्रतिशत से अधिक दर्ज की गई।

[42] इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा पाम तेल उत्पादक है, ने हाल ही में डीज़ल में पाम तेल मिश्रण के लक्ष्यों को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। (उल्लेखनीय: https://setkab.go.id/en/govt-launches-mandatory-b50-biodiesel-affirms-national-preparedness-to-strengthen-energy-sovereignty/)

चार्ट III.11:जुलाई में खाद्य कीमतों पर व्यापक दबाव



टिप्पणी: डेटा 01-20 जुलाई, 2026 तक का है, और पिछले महीने की इसी अवधि की तुलना में औसत कीमतों में माह-दर-माह हुए बदलाव को दिखाता है।
स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार; और आरबीआई स्टाफ की गणना।

जुलाई में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें अपरिवर्तित रहीं। घरेलू एलपीजी की कीमतें भी जुलाई[43] में स्थिर रहीं (सारणी III.6)। भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की कीमत[44] अप्रैल[45] में 114.5 अमेरिकी डॉलर के शिखर से जुलाई में (20 तक) घटकर 75.6 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गई (चार्ट III.12)।

सारणी III.6: स्थिर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें

वस्तु	इकाई	घरेलू कीमतें			माह-दर-माह (प्रतिशत)	
		जुला-25	जून-26	जुला-26 ^	जून-26	जुला-26 ^
पेट्रोल	₹/लीटर	101.1	108.7	108.7	4.4	0.0
डीज़ल	₹/लीटर	90.5	98.1	98.1	5.0	0.0
मिट्टी का तेल (सब्सिडी)	₹/लीटर	43.0	46.8	46.8	0.0	0.0
एलपीजी (गैर-सब्सिडी)	₹/सिलेंडर	863.3	946.5	952.3	2.5	0.6

- ^: 01-20 जुलाई, 2026 की अवधि के लिए।
टिप्पणी: केरोसिन के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में औसत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की कीमतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। केरोसिन के लिए, कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में सब्सिडी वाली कीमतों के औसत को दर्शाती हैं।
स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ की गणना।

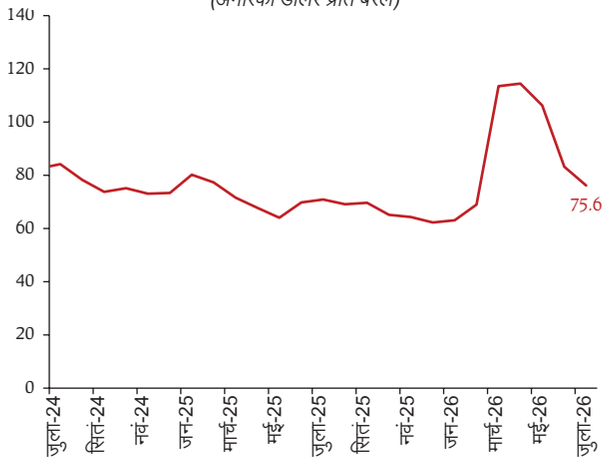
[43] 07 जून, 2026 को घरेलू घरेलू एलपीजी की कीमतों को ₹29 प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर बढ़ाकर ₹952 कर दिया गया।

डबल्यूपीआई मुद्रास्फीति जून 2026 में बढ़कर 9.9 प्रतिशत हो गई, जो मई 2026 में 9.7 प्रतिशत थी (अनुबंध बॉक्स 1 देखें)। ईंधन और बिजली समूह में मुद्रास्फीति जून 2026 में 27.4 प्रतिशत पर बनी रही। प्राथमिक वस्तुओं में मुद्रास्फीति जून 2026 में बढ़कर 7.0 प्रतिशत हो गई, जो मई 2026 में 5.0 प्रतिशत थी। इनपुट मूल्य दबाव, जैसा कि औद्योगिक लागत

[44] इसमें भारतीय रिफाइनरी द्वारा मासिक आधार पर आयातित मीठे ग्रेड (ब्रेंट दिनांकित) और खट्टे ग्रेड (ओमान और दुबई औसत) का व्युत्पन्न बास्केट दर्शाया गया है, जिसका अनुपात अप्रैल में 61:39, मई में 70:30, जून में 71:29 और जुलाई में 79:21 था।
[45] औसत मासिक कीमत को दर्शाता है।

चार्ट III. 12: जुलाई में इंडियन बास्केट क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी आई

(अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल)



टिप्पणी: 1. डेटा 20 जुलाई तक है।
2. डेटा महीने का औसत दिखाता है।

स्रोत: पीपीएसी।

मुद्रास्फीति में परिलक्षित होता है, ऊंचा बना रहा, जबकि कृषि इनपुट में वृद्धि दर्ज की गई।[46]

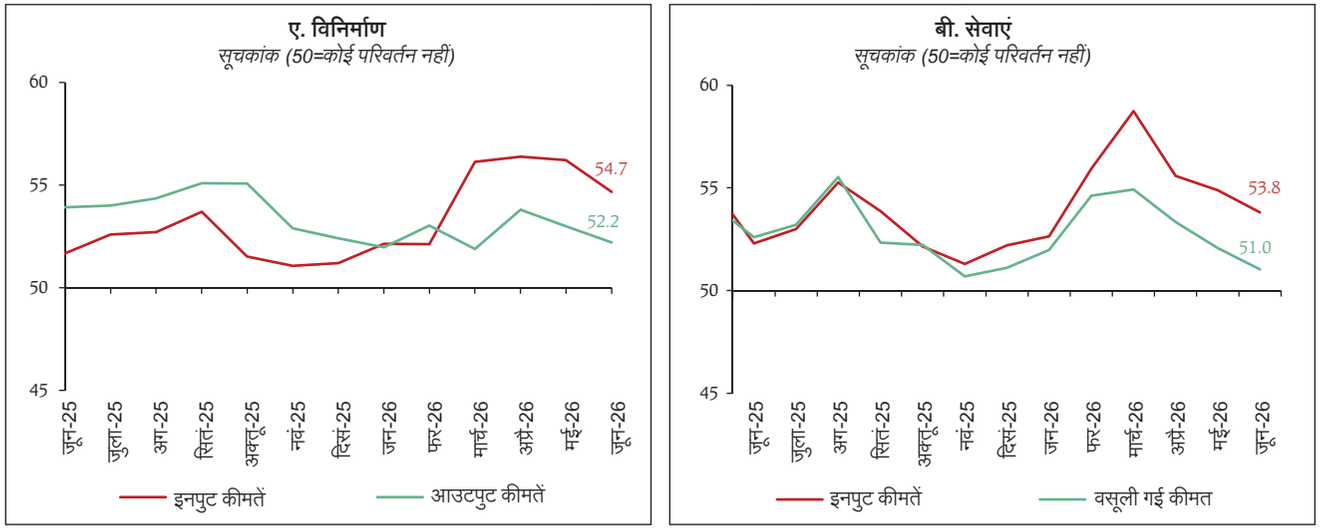
उत्पादन उत्पादक कीमत सूचकांक (ओपीपीआई) के अनुसार, जून में महंगाई दर बढ़कर 9.6 प्रतिशत (व-द-व) हो गई, जो पिछले माह 9.4 प्रतिशत थी। इसमें मुख्य रूप से 'कृषि, वानिकी और मछली पालन' क्षेत्रों का योगदान रहा।

विनिर्माण फर्मों के लिए इनपुट कीमतों के लिए पीएमआई ने एक अनुक्रमिक सहजता दर्ज की, जबकि विस्तारवादी चरण में शेष रहा। विनिर्माण फर्मों के लिए आउटपुट कीमतों के लिए पीएमआई भी धीमी गति से कम हो गया, जिससे इनपुट और आउटपुट कीमतों के विस्तार के बीच अंतर कम हो गया। सेवा क्षेत्र में भी, आउटपुट और इनपुट कीमतों दोनों के लिए पीएमआई क्रमिक रूप से नियंत्रित हुए, हालांकि विस्तारवादी क्षेत्र में बने रहे (चार्ट III.13).

IV. वित्तीय स्थितियां

जून के हल्के अधिशेष से, जुलाई के पहले पखवाड़े में प्रणालीगत चलनिधि[47] में सुधार हुआ।[48] जून के पहले पखवाड़े में

चार्ट III. 13: जून में इनपुट और आउटपुट की कीमतें कम हुईं



टिप्पणी: 50 का लेवल एक्टिविटी में कोई बदलाव नहीं दिखाता है, और 50 से ऊपर का रीडिंग बढ़ोतरी दिखाता है और इसके विपरीत।

स्रोत: एसएंडपी।

[46] जून 2026 में औद्योगिक और कृषि इनपुट लागत मुद्रास्फीति, क्रमशः 16.2 प्रतिशत और 11.7 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि मई 2026 में यह 16.7 प्रतिशत और 8.9 प्रतिशत थी। औद्योगिक इनपुट लागत सूचकांक में प्राथमिक गैर-खाद्य वस्तुएं, खनिज, कोयला, विमानन टरबाइन ईंधन, हाई स्पीड डीजल, नेफ्था, बिटुमेन, भट्ठा तेल, लुब्रिकेंट तेल, पेट्रोलियम कोक, विद्युत, कॉटन यार्न और कागज एवं लुगदी शामिल हैं। कृषि इनपुट लागत सूचकांक में हाई-स्पीड डीजल, चारा, विद्युत, उर्वरक, कीटनाशक और कृषि एवं वानिकी मशीनरी शामिल हैं।

[47] यह चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत औसत दैनिक निवल अवशोषण के माध्यम से मापा गया है।

[48] कुल मिलाकर, एलएएफ़ के तहत दैनिक औसत निवल अवशोषण जुलाई (20 जुलाई तक) में ₹1.25 लाख करोड़ तक बढ़ गया, जो जून में ₹0.89 लाख करोड़ था।

स्थिति सहज रहने के बाद, महीने के दूसरे पखवाड़े में अग्रिम कर और जीएसटी से संबंधित बहिर्वाह के बीच चलनिधि अधिशेष कम हो गया और थोड़े समय के लिए घाटे में चला गया। जुलाई के पहले पखवाड़े में चलनिधि की स्थिति में औसतन सुधार हुआ, क्योंकि कर बहिर्वाह का दबाव कम हुआ और सरकारी खर्च में तेजी आई, जिसके बाद जुलाई के दूसरे पखवाड़े (20 जुलाई तक) में यह कठोर हो गई। जून-जुलाई के दौरान चलनिधि की अल्पकालिक कमी से निपटने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 परिवर्तनीय-दर रेपो नीलामियां आयोजित कीं।49 बैंकों ने स्थायी जमा सुविधा के तहत बड़े अधिशेष फंड जमा करना जारी रखा, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा का उपयोग स्थिर बना रहा (चार्ट IV.1)।[50]

मुद्रा बाजार

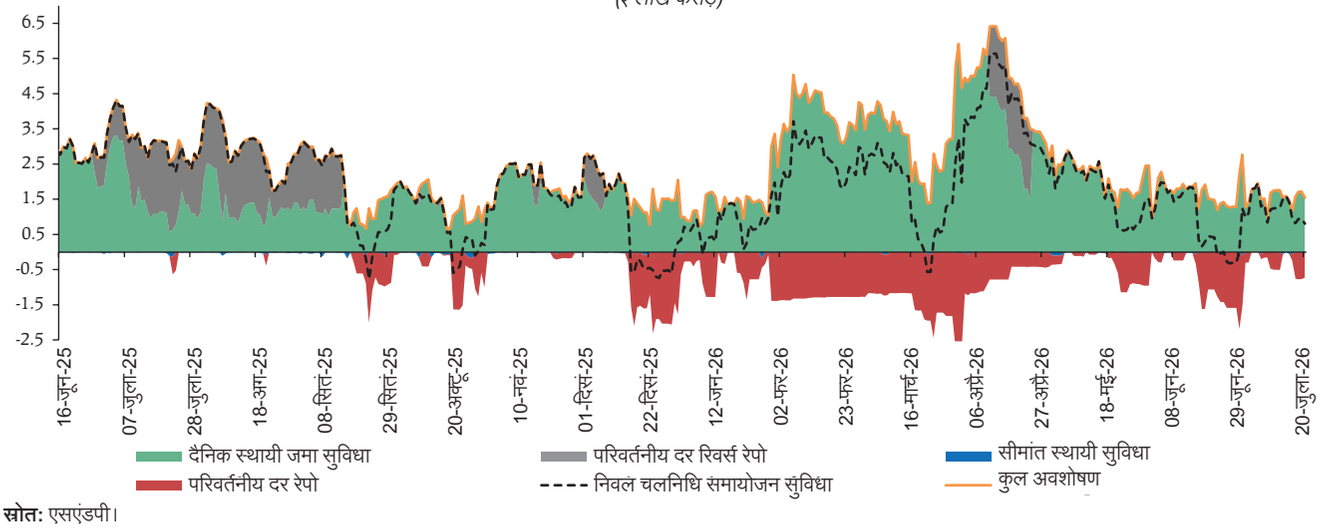
जून और जुलाई के महीनों में, भारित औसत कॉल दर (डबल्यूएसीआर) नीति गलियारे के ऊपरी आधे हिस्से में मंडराती रही। जुलाई में चलनिधि की स्थिति में सुधार होने पर, यह नीति दर के करीब कारोबार करती रही (चार्ट IV.2ए)।[51] संपार्श्विक ओवरनाइट खंड में दरें डबल्यूएसीआर के साथ-साथ चलीं। जून की तुलना में जुलाई की शुरुआत में ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और जमा प्रमाणपत्र (सीडी) पर प्रतिफल नरम हो गए (चार्ट IV.2बी)।[52] तथापि, 8 जुलाई को पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम के टूटने के पश्चात, मुद्रा बाजार की दरें सख्त हो गईं। जुलाई के दूसरे सप्ताह में जमा प्रमाणपत्र (सीडी) की दरों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई, जो कि अधिशेष चलनिधि में नरमी और ऋण वृद्धि द्वारा जमा वृद्धि को पीछे छोड़ने के कारण बने निरंतर वित्तपोषण दबावों के बीच हुई। 3-महीने के वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और 91-दिवसीय ट्रेजरी बिल की यील्ड के बीच का औसत अंतर कम हो गया।[53].

सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाज़ार

पश्चिम एशिया में तनाव कम होने तथा भारतीय ऋण बाजारों में विदेशी पूंजी आकर्षित करने के वास्ते सरकार और रिजर्व बैंक के उपायों के कारण जून और जुलाई के आरंभ में विभिन्न

चार्ट IV. 1: जुलाई में प्रणाली चलनिधि में सुधार हुआ

(₹ लाख करोड़)



स्रोत: एसएंडपी।

[49] जून में, आरबीआई ने 13 वीआरआर नीलामियों का संचालन किया, जिनकी परिपक्वता अवधि ओवरनाइट से 7 दिनों तक थी, जिसमें औसत बोली-आवरण अनुपात 0.54 था। इसके अतिरिक्त, जुलाई (20 जुलाई तक) में आरबीआई ने 10 वीआरआर नीलामियों का संचालन किया, जिसमें औसत बोली-आवरण अनुपात 0.48 था।

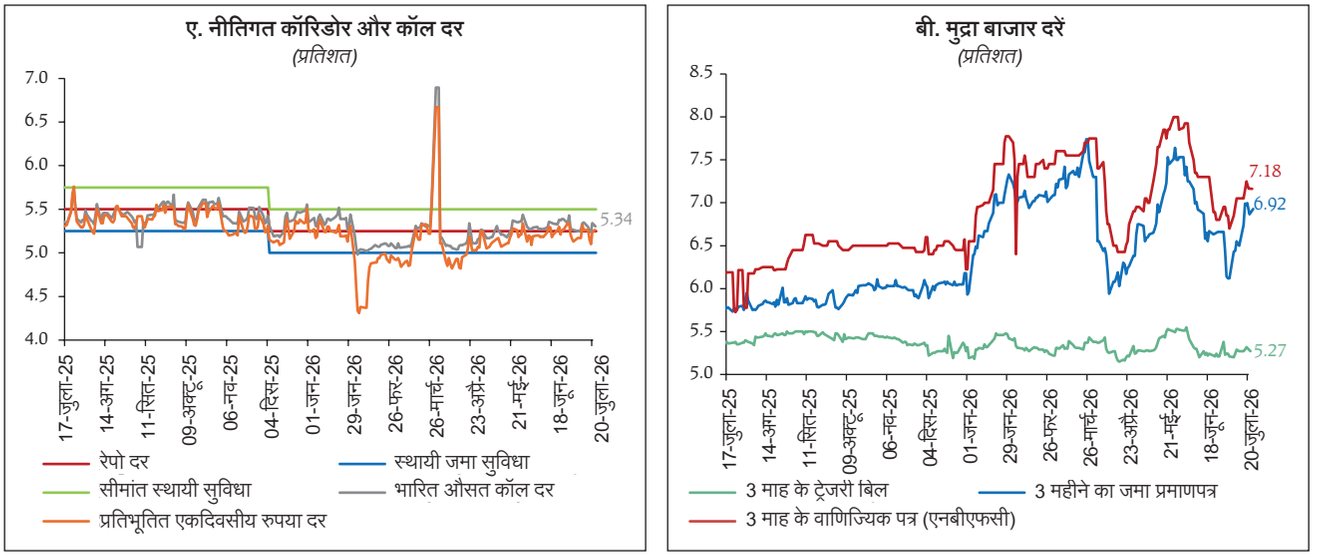
[50] स्थायी जमा सुविधा के तहत औसत शेष राशि जुलाई (20 जुलाई तक) में ₹1.58 लाख करोड़ तक मामूली रूप से घट गई, जो जून में ₹1.68 लाख करोड़ थी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत उधारी जुलाई (20 जुलाई तक) में औसतन ₹0.01 लाख करोड़ रही, जो जून में इसी स्तर पर थी।

[51] औसतन, डबल्यूएसीआर जुलाई (20 जुलाई तक) में 5.29 प्रतिशत तक मामूली रूप से कम हो गया, जो जून में 5.32 प्रतिशत था।

[52] 3-महीने के ट्रेजरी बिल, 3-महीने के डिपाजिट सर्टिफिकेट और एनबीएफ़सी द्वारा जारी 3-महीने के कमर्शियल पेपर्स पर औसत प्रतिफल जुलाई (20 जुलाई तक) में क्रमशः 3 बीपीएस, 29 बीपीएस और 28 बीपीएस कम हो गई, जून की तुलना में।

[53] जून में 200 बेसिस पॉइंट से घटकर जुलाई (20 जुलाई तक) में औसतन 176 बेसिस पॉइंट पर आ गई।

चार्ट IV.2: डबल्यूएसीआर कॉरिडोर के अंदर ट्रेड हुआ और मुद्रा बाज़ार दरों में बढ़ोतरी आरंभ हुई

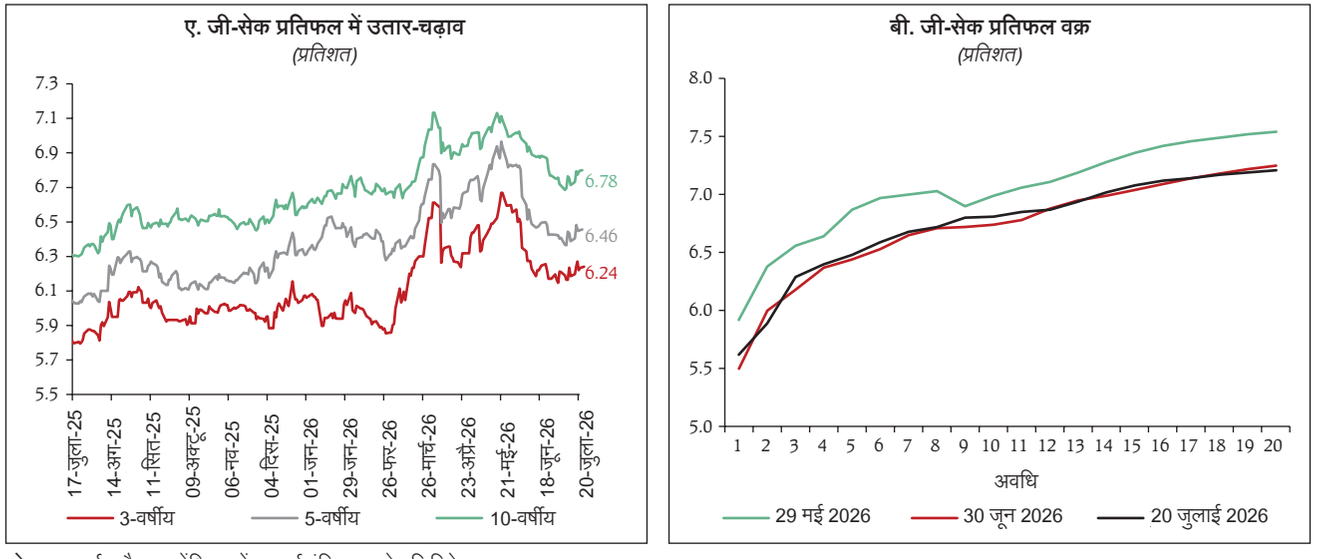


स्रोत: आरबीआई; ब्लूमबर्ग।

परिपक्वता अवधि वाले सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) प्रतिफल में नरमी आई। तथापि, पश्चिम एशिया का संघर्ष दोबारा भड़कने के बाद प्रतिफल में मामूली तेजी आई (चार्ट IV.3)।[54]

केंद्र सरकार ने तुलनीय परिपक्वता वाले सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) के द्वितीयक बाजार प्रतिफल से जुड़ी विभिन्न लघु बचत उपकरणों की ब्याज दरों की समीक्षा की और उन्हें वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के लिए अपरिवर्तित रखा।[55] लोक भविष्य निधि (पीपीएफ़) को छोड़कर, इन उपकरणों पर प्रचलित दरें उनके सूत्र-आधारित दरों से अधिक हैं।

चार्ट IV.3: जुलाई के दौरान जी-सेक प्रतिफल में थोड़ी सी बढ़त दर्ज़ की गई।



स्रोत: ब्लूमबर्ग: और फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।

[54] 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर सामान्य यील्ड 20 जुलाई, 2026 को 6.78 प्रतिशत रही, जो 30 जून, 2026 को 6.75 प्रतिशत के मुकाबले अधिक है। यह यील्ड मई 2026 के अंत में 7.00 प्रतिशत थी।

[55] https://dea.gov.in/files/budget_division_documents/Q2ROI.pdf

कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार

अप्रैल की अपेक्षा मई में नए कॉर्पोरेट बॉन्ड निर्गमों में वृद्धि हुई। संचयी आधार पर, चालू वित्त वर्ष में कुल निर्गम कम बने रहे।[56] सरकारी बॉन्ड यील्ड (सारणी IV.1) में आई नरमी के अनुरूप, जुलाई में (20 जुलाई तक) विभिन्न परिपक्वता अवधियों और रेटिंग स्पेक्ट्रम में औसत कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड नरम हुई।

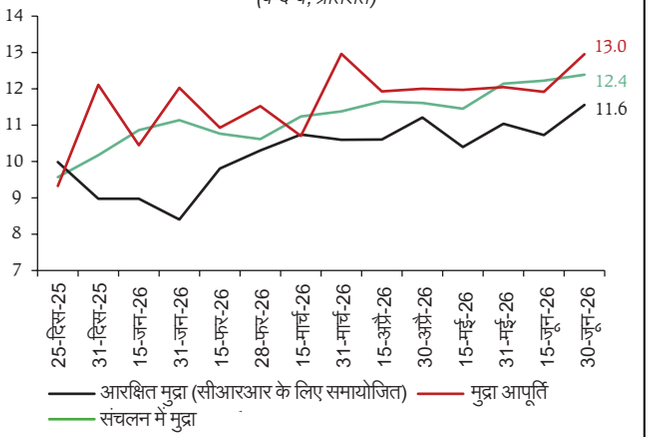
मुद्रा और ऋण

जून 2026 में आरक्षित मुद्रा (नकद आरक्षित अनुपात के लिए समायोजित) में वृद्धि जारी रही, और दिसंबर 2025 से चलन में मौजूद मुद्रा में दो अंकों की वृद्धि बनी रही।[57] जून 2026 में मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई (चार्ट IV.4)।[58].

जून के महीने में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण और जमा की वृद्धि दर बढ़ी, और सितंबर 2025 से ऋण वृद्धि लगातार जमा वृद्धि से अधिक बनी हुई है। फिर भी, वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात कम हुआ (चार्ट IV.5)।[59]

चार्ट IV.4: आरक्षित मुद्रा और मुद्रा आपूर्ति (एम3) में लगातार बढ़ोतरी

(व-द-व, प्रतिशत)



टिप्पणी: बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के ज़रिए पखवाड़े की परिभाषा में बदलाव के साथ, आरक्षित मुद्रा और मुद्रा आपूर्ति का डेटा माह के 15वें और आखिरी दिन से जुड़ा होगा, जो 15 दिसंबर 2025 से लागू होगा।
स्रोत: आरबीआई।

वर्ष 2026-27 (30 जून तक) के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का कुल प्रवाह काफी बढ़ गया, जिसके पीछे गैर-खाद्य बैंक ऋण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई)[60] का समर्थन था [सारणी IV.2ए और बी]।

सारणी IV.1: जुलाई में कॉर्पोरेट बॉन्ड पर औसत प्रतिफल में नरमी

लिखत	*ब्याज दरें (प्रतिशत)*			*स्प्रेड (आधार अंक)*		
	जून 2026	जुलाई 2026 (20 जुलाई तक)	भिन्नता	जून 2026	जुलाई 2026 (20 जुलाई तक)	भिन्नता
1	2	3	(4 = 3-2)	5	6	(7 = 6-5)
(i) एएए (1 वर्ष)	7.61	7.39	-22	173	168	-5
(ii) एएए (3 वर्ष)	7.54	7.42	-12	114	110	-4
(iii) एएए (5 वर्ष)	7.65	7.49	-16	93	93	0
(iv) एए (3 वर्ष)	8.34	8.21	-13	194	189	-5
(v) बीबीबी (3-वर्ष)	11.95	11.80	-15	555	548	-7

टिप्पणी: प्रतिफल और स्प्रेड की गणना संबंधित अवधि के लिए औसत के रूप में की जाती है।
स्रोत: एफ़आईएमएमडीए।

[56] मई 2026 में जारी राशि ₹0.51 लाख करोड़ रही, जो अप्रैल 2026 में ₹0.35 लाख करोड़ थी। संचयी आधार पर, यह अप्रैल-मई: 2026-27 में ₹0.86 लाख करोड़ पर रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में ₹1.87 लाख करोड़ से कम है।

[57] आरक्षित धन में वृद्धि (कैश रिज़र्व रेश्यो में परिवर्तन के प्रथम चरण के प्रभाव के लिए समायोजित) 30 जून, 2026 को 11.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) तक बढ़ गई, जबकि 31 मई, 2026 को यह 11.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) थी। परिसंचरण में मुद्रा में वृद्धि 30 जून, 2026 को 12.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) तक बढ़ गई, जबकि 31 मई, 2026 को यह 12.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) थी [31 दिसंबर, 2025 को 10.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष)]।

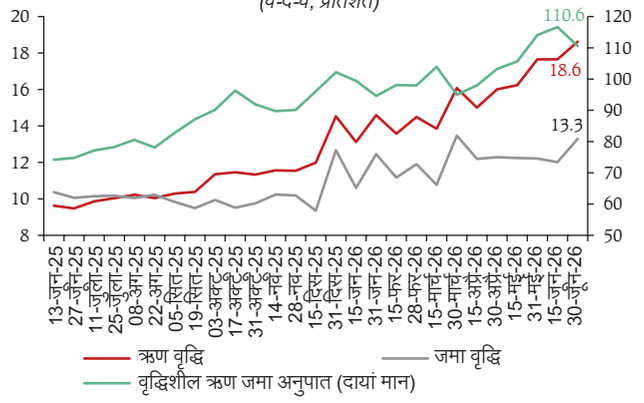
[58] मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि 30 जून, 2026 को 13.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) तक बढ़ गई, जबकि 31 मई, 2026 को यह 12.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) थी।

[59] एससीबीज़ के क्रेडिट और जमा की वृद्धि क्रमशः 30 जून, 2026 को 18.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) और 13.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) तक बढ़ गई, जबकि 31 मई, 2026 को यह क्रमशः 17.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) और 12.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) थी।

[60] भारत में एफडीआई निवल आधार पर है (अर्थात, सकल प्रवाह को पुनर्प्रेषण/विनिवेश के लिए समायोजित किया गया है)।

चार्ट IV.5: एससीबी की ऋण और जमा वृद्धि में और तेजी आई

(व-द-व, प्रतिशत)



टिप्पणी: 1. एससीबी के डेटा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शामिल हैं। डेटा में एक गैर-बैंक के बैंक में विलयन का असर भी शामिल है।
2. बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के माध्यम से पखवाड़े की परिभाषा में बदलाव के साथ, एससीबी के लिए डेटा माह के 15 वें और अंतिम दिन से संबंधित है, जो 15 दिसंबर 2025 से प्रभावी है।

स्रोत: आरबीआई।

मई 2026 के दौरान प्रमुख क्षेत्रों में बैंक ऋण में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई।[61] कृषि क्षेत्र को ऋण में तेजी आई, और बड़े उद्योगों को ऋण विस्तार के साथ औद्योगिक ऋण वृद्धि ने अपनी गति बनाए रखी। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) को बैंक ऋण दिए जाने के कारण सेवा क्षेत्र में भी ऋण प्रवाह मजबूत हुआ। अप्रैल 2026 की तुलना में आवास, वाहन और स्वर्ण जैसे खंडों में व्यक्तिगत ऋण की गति धीमी रही (चार्ट IV.6)।

मई 2026 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) द्वारा दिए जाने वाले ऋण में उद्योग को छोड़कर सभी प्रमुख क्षेत्रों में साल-दर-साल आधार पर दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई।[62] कृषि ऋण में जहां मजबूत गति से विस्तार हुआ, वहीं बुनियादी ढांचा क्षेत्र (जो उद्योग का सबसे बड़ा खंड है) के ऋण में आई सुस्ती के कारण औद्योगिक ऋण की वृद्धि धीमी हो गई।

सारणी IV.2ए: वाणिज्यिक क्षेत्रों में वित्तीय संसाधनों के प्रवाह में बढ़ोतरी

(₹ लाख करोड़)

लिखत	*अप्रैल-मार्च*		*28 फरवरी तक*	
	2024-25	2025-26	2025-26	2026-27 पी
ए. गैर-खाद्य बैंक ऋण	**18.08**	**29.19**	**0.50**	**5.05**
बी. गैर-बैंक स्रोत (बी1+बी2)	**18.15**	**17.69**	**2.62**	**2.68**
बी 1. घरेलू स्रोत	14.91	12.66	1.69	0.96
बी 2. विदेशी स्रोत	3.25	5.03	0.94	1.72
सी. संसाधनों का कुल प्रवाह (ए+बी)	**36.23**	**46.88**	**3.12**	**7.73**

पी: अनंतिम।

टिप्पणी: 1. संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़े कुल में नहीं जुड़ सकते हैं।
2. विस्तृत नोट्स और डेटा के लिए, कृपया वर्तमान सांख्यिकी सारणी संख्या: 18 (ए) देखें।

स्रोत: आरबीआई; सेबी; एआईएफआई; और आरबीआई स्टाफ की गणना।

सारणी IV.2बी: वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए उच्च बकाया ऋण

(₹ लाख करोड़; कोष्ठक में आंकड़े व-द-व प्रतिशत परिवर्तन हैं)

स्रोत	*मार्च के अंत में*		*30 जून तक*	
	2025	2026	2025	2026 P
ए. गैर-खाद्य बैंक ऋण	**183.72**	**212.91**	**184.22**	**217.96**
	(10.9)	**(15.9)**	**(9.3)**	**(18.3)**
बी. गैर-बैंक स्रोत (बी1+बी2)	**88.86**	**101.59**	**90.28**	**102.94**
	(14.6)	**(14.3)**	**(15.5)**	**(14.0)**
बी 1. घरेलू स्रोत	66.37	75.11	67.55	75.84
	(17.3)	(13.2)	(18.3)	(12.3)
बी 2. विदेशी स्रोत	22.49	26.48	22.73	27.09
	(7.2)	(17.7)	(8.0)	(19.2)
सी. कुल ऋण (ए+बी)	**272.58**	**314.50**	**274.50**	**320.90**
	(12.1)	**(15.4)**	**(11.3)**	**(16.9)**

पी: अनंतिम।

टिप्पणी: 1. संख्याओं को पूर्णांकित करने के कारण कॉलमों में आंकड़े कुल में नहीं जुड़ सकते हैं।
2. गैर-बैंक स्रोतों पर डेटा में घरेलू स्रोतों के तहत इक्विटी और हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स जारी करना और विदेशी स्रोतों के तहत इक्विटी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शामिल नहीं है।
3. बकाया डेटा पर आधारित प्रवाह सारणी IV.2ए में दिए गए प्रवाह के साथ मेल नहीं खा सकता है:
(ए) कुछ आवास वित्त कंपनियों का गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में परिवर्तन; तथा
(बी) विदेशी स्रोतों के मामले में मूल्यांकन प्रभाव।
4. विस्तृत नोट्स और डेटा के लिए, कृपया वर्तमान सांख्यिकी सारणी संख्या: 18 (बी) देखें।

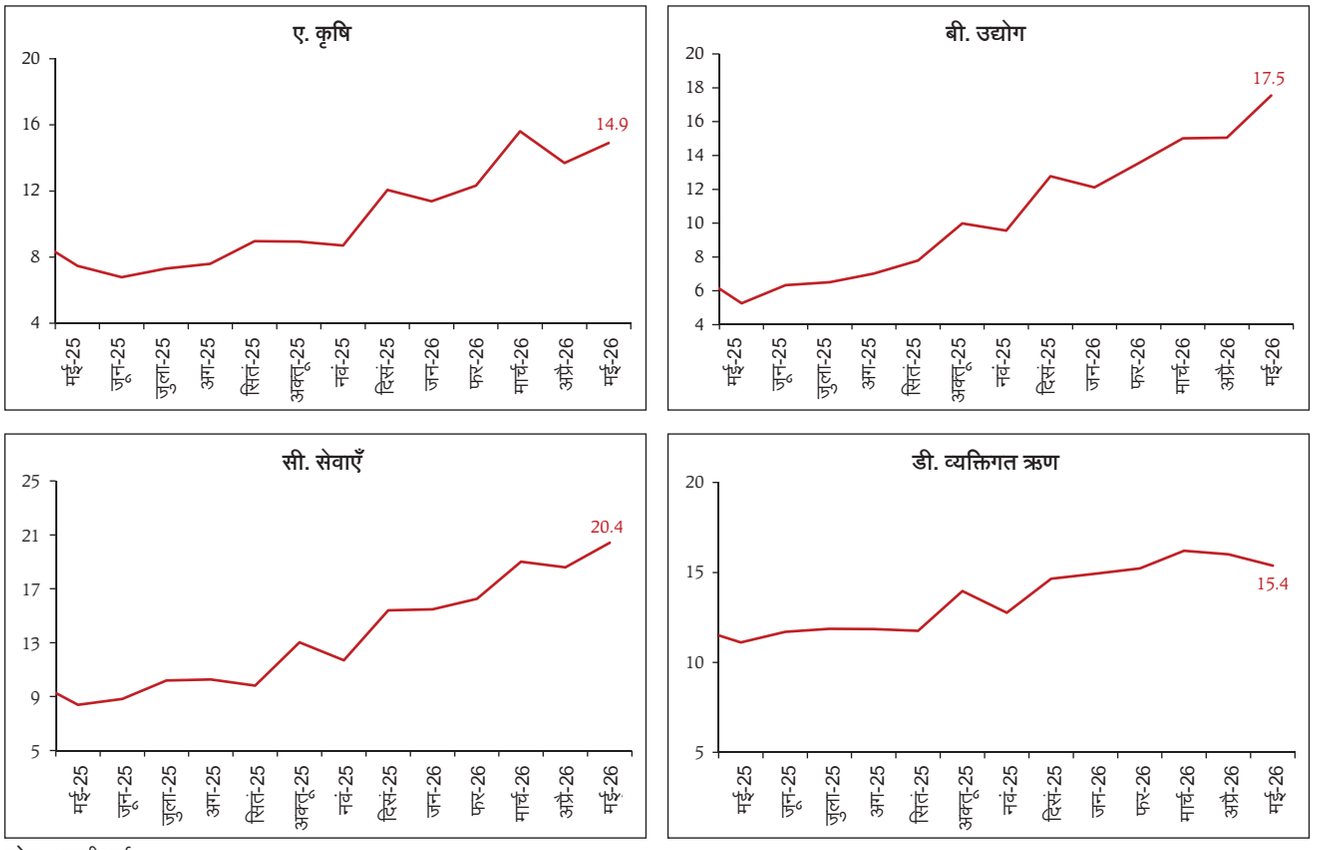
स्रोत: आरबीआई; सेबी; एआईएफआई; और आरबीआई स्टाफ की गणना।

[61] बैंक क्रेडिट के क्षेत्रीय वितरण पर अस्थायी आंकड़े क्षेत्र-वार और उद्योग-वार बैंक क्रेडिट (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित हैं, जो 41 चयनित बैंकों को कवर करता है, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा प्रदान किए गए कुल गैर-खाद्य क्रेडिट का लगभग 95 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं। 31 दिसंबर, 2025 से प्रभावी, अंतिम रिपोर्टिंग पखवाड़े की परिभाषा बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत माह के अंतिम दिन में बदल दी गई है। तदनुसार, दिसंबर 2025 से वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दरें वर्तमान वर्ष के माह अंत के डेटा और पिछले वर्ष के संबंधित महीने के अंतिम रिपोर्टिंग पखवाड़े (पुरानी परिभाषा के अनुसार) के डेटा पर आधारित हैं। गैर-खाद्य क्रेडिट की वृद्धि की गणना पखवाड़ेवार सेक्शन-42 रिटर्न के आधार पर की जाती है, जो सभी एससीबी को कवर करता है।

[62] उपलब्ध अस्थायी डेटा महीने के अंतिम दिन की रिपोर्ट के आधार पर। एनबीएफ़सी का क्षेत्रीय ऋण डेटा निम्नलिखित नमूनों पर आधारित है: (i) ऊपरी और मध्य परतों में एनबीएफ़सी और (ii) एचएफ़सी जो कि कुल ऋण का लगभग 87 प्रतिशत बनाते हैं, जैसा कि 'भारत में बैंकिंग के रुझान और प्रगति पर रिपोर्ट 2024-25' (आरटीपी 2024-25, सितंबर 2025 तक बकाया) में प्रकाशित डेटा के अनुसार है।

चार्ट IV.6: बैंक क्रेडिट का क्षेत्रवार विनियोजन

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)



स्रोत: आरबीआई।

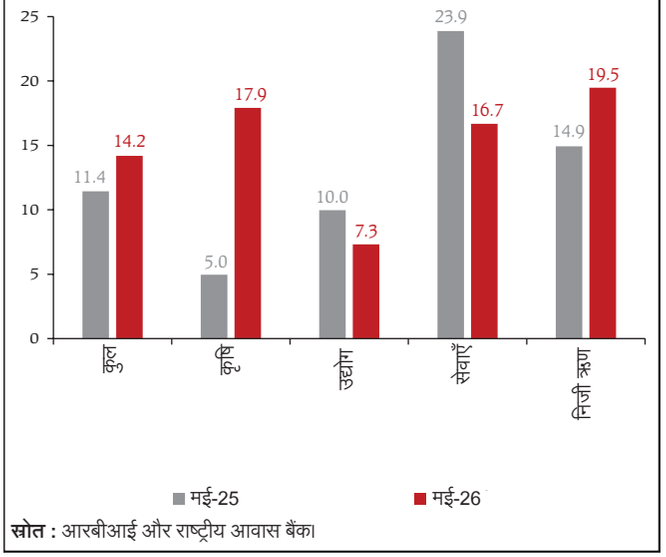
वाणिज्यिक रियल एस्टेट खंड को ऋण में तेजी के बावजूद, सेवा क्षेत्र को ऋण की वृद्धि मुख्य रूप से व्यापार और परिवहन ऑपरेटर खंडों के कारण धीमी हो गई। सोने के आभूषणों और आवास ऋणों[63] में मजबूत वृद्धि से खुदरा ऋणों में तेजी आई, जबकि वाहन ऋणों की वृद्धि में मामूली नरमी आई (चार्ट IV.7)।

जमा और ऋण की दरें

वर्तमान ढील चक्र (फरवरी 2025 - मई 2026) के दौरान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) ने रेपो-संबद्ध बाहरी बेंचमार्क आधारित ऋण दरों (ईबीएलआर) और सीमांत निधि लागत आधारित ऋण दरों (एमसीएलआर) दोनों में कटौती की है (सारणी IV.3)। बुनियादी ढांचे के क्षेत्र और ईबीएलआर-अनिवार्य

चार्ट IV.7 : बैंक ऋण वृद्धि स्थिर रही

(व-द-व, प्रतिशत)



स्रोत : आरबीआई और राष्ट्रीय आवास बैंक।

[63] आवास ऋण डेटा में हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफ़सी) से आवास ऋण भी शामिल हैं।

सारणी IV.3: बैंकों की जमा और उधार दरों में संचरण

(आधार अंक)

अवधि	रेपो दर	*सावधि जमा दरें*		*ऋण दरें*				
		डबल्यूएडीटी डीआर-नया जमा	डबल्यूए डीटीडीआर -बकाया जमा	ईबीएलआर	1-वर्षीय एमसीएलआर (माध्यिका) कुल मिलाकर	डबल्यूएएलआर - नया रुपया ऋण		डबल्यूएएलआर -बकाया रुपया ऋण
						कुल मिलाकर	ब्याज दर प्रभाव #	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
सख्ती चक्र मई 2022 से जनवरी 2025 तक	250	259	206	250	175	182	191	115
सहजता चक्र फरवरी 2025 से मार्च 2026 तक	-125	-78	-52	-125	-35	-82	-85	-90

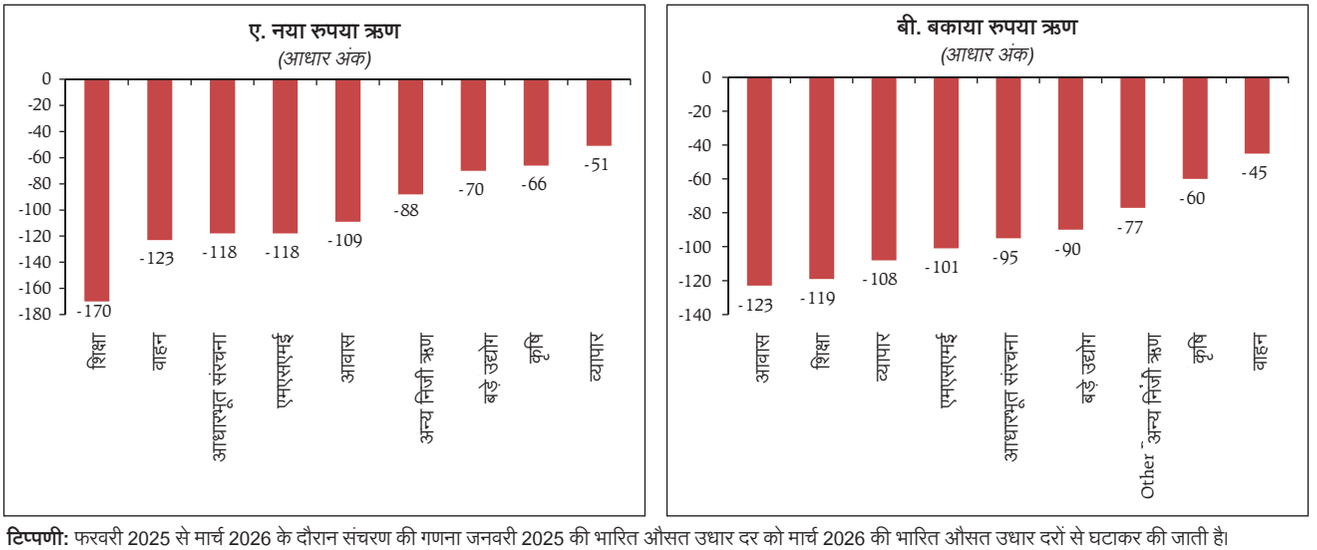
#: जनवरी 2025 के भार पर गणना की गई।
डबल्यूएएलआर: भारित औसत ऋण दर; डब्ल्यूएडीटीडीआर; भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर;
एमसीएलआर: फंड की सीमांत लागत-आधारित उधार दर; ईबीएलआर: बाह्य बेंचमार्क-आधारित उधार दर।
टिप्पणी: ईबीएलआर पर आंकड़े 32 घरेलू बैंकों से संबंधित हैं।
स्रोत: आरबीआई।

क्षेत्रों में नए ऋण दरों पर इसका प्रभाव मजबूत था (चार्ट IV.8)।[64] घरेलू बैंकों में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में निजी क्षेत्र के बैंकों ने ऋण दरों पर अधिक प्रभाव दिखाया। विदेशी बैंकों के लिए जमा और ऋण दोनों दरों पर यह प्रभाव अधिक रहा है (चार्ट IV.9)।

इक्विटि बाज़ार

जून और जुलाई के शुरुआती हफ़्तों में भारतीय इक्विटि बाज़ारों में बढ़त दर्ज की गई, जो अमेरिका-ईरान संघर्ष-विराम समझौते के बाद सुधरे हुए माहौल, कच्चे तेल के नरम पड़ते दामों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफ़पीआई) द्वारा (जून के मध्य से) निवल लिवाली में आए सुधार को दर्शाती है [चार्ट IV.10]। 8 जुलाई को पश्चिम एशिया में संघर्ष-विराम समाप्त होने की घोषणा के साथ ही, कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों के बीच शेयर बाज़ारों में गिरावट आई।[65] इसके बाद से बाज़ार एक निश्चित दायरे में ही कारोबार कर रहा है।

चार्ट IV.8: चुनिंदा क्षेत्रों में संचरण (फरवरी 2025-मई 2026)

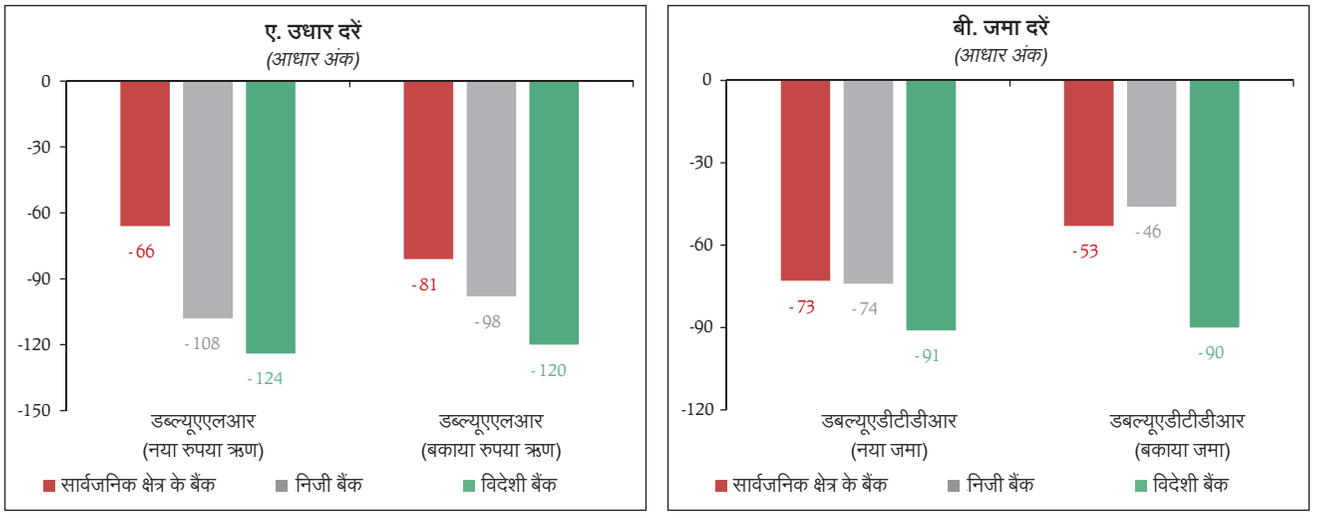


टिप्पणी: फरवरी 2025 से मार्च 2026 के दौरान संचरण की गणना जनवरी 2025 की भारित औसत उधार दर को मार्च 2026 की भारित औसत उधार दरों से घटाकर की जाती है।
स्रोत: आरबीआई।

[64] ईबीएलआर-अधिकृत क्षेत्रों में शिक्षा, वाहन, एमएसएमई, आवास और अन्य व्यक्तिगत ऋण शामिल हैं।

[65] भारत VIX मई 2026 के अंत में 16.2 से घटकर जून के अंत में 13.6 और 07 जुलाई, 2026 को 11.7 हो गया। यह 08 जुलाई को 14.7 तक बढ़ा, इसके बाद 20 जुलाई, 2026 को गिरकर 13.0 हो गया।

चार्ट IV.9: बैंक समूहों में संचरण (फरवरी 2025-मई 2026)

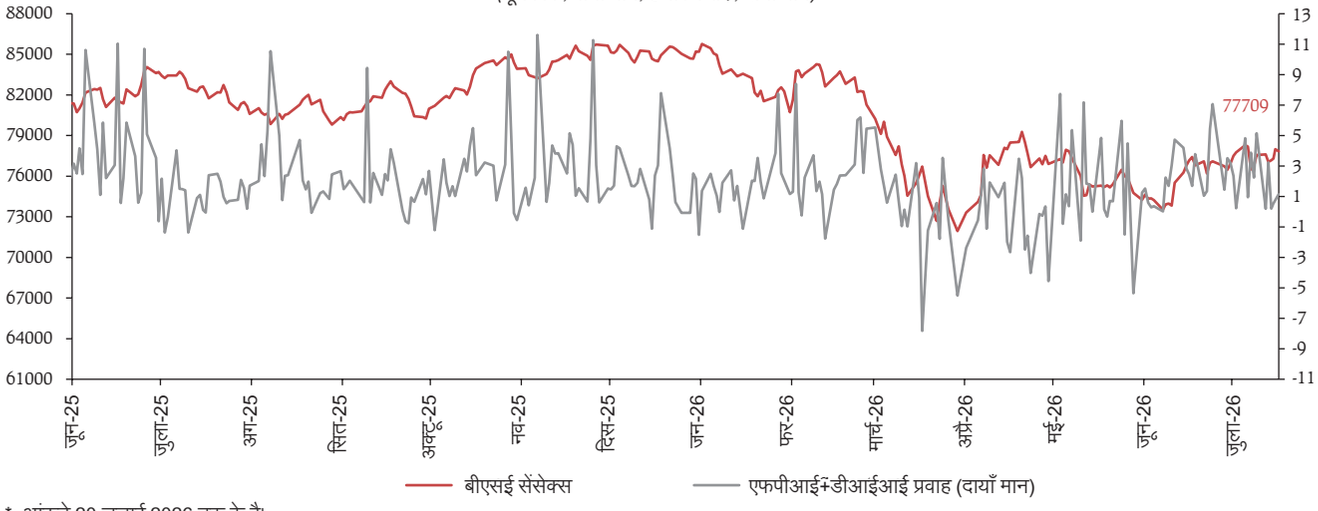


टिप्पणी: फरवरी 2025 से मई 2026 के दौरान संचरण की गणना जनवरी 2025 के भारित-औसत उधार और जमा दर को मई 2026 घटाकर की जाती है।
स्रोत: आरबीआई।

वित्त के बाहरी स्रोत

अप्रैल-मई 2026 के दौरान, कम प्रत्यावर्तन (पूंजी की वापसी) के समर्थन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई) सकल और निवल दोनों ही रूपों में अधिक बना रहा (चार्ट IV.11ए)।[66] जापान, सिंगापुर और मॉरीशस की कुल इक्विटी अंतर्वाह में हिस्सेदारी लगभग 74 प्रतिशत रही। वित्तीय सेवाओं को इक्विटी अंतर्वाह का सबसे बड़ा हिस्सा मिला, उसके बाद विनिर्माण, खुदरा और थोक व्यापार, और कंप्यूटर सेवाओं का स्थान रहा;

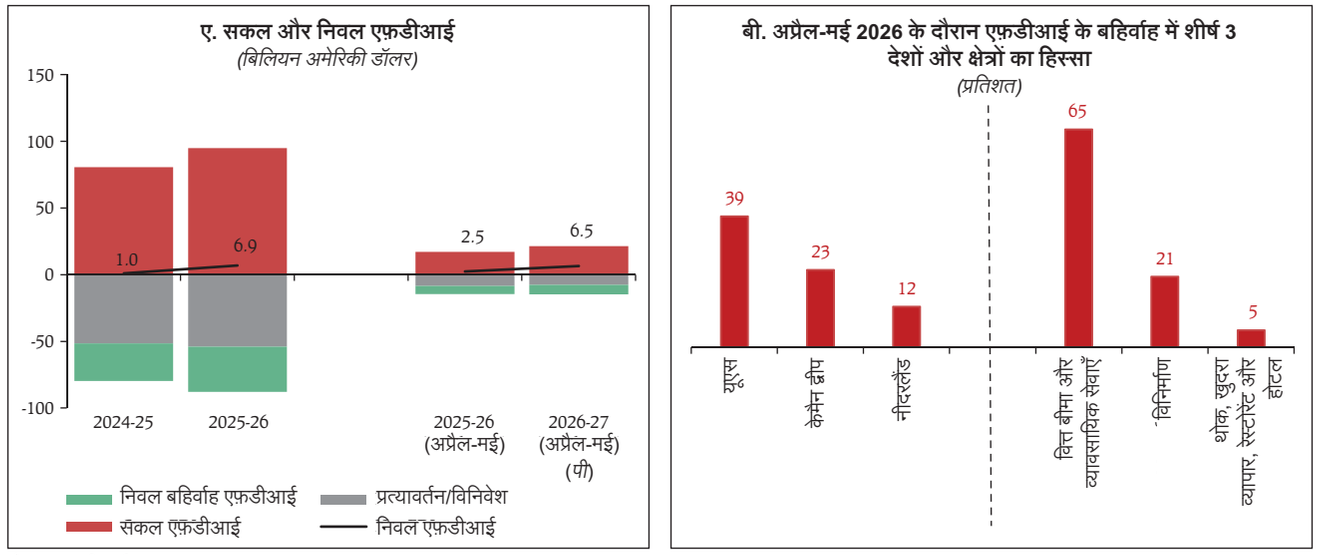
चार्ट IV.10: जून और जुलाई के शुरुआत में घरेलू इक्विटि बाज़ार में तेज़ी आई।
(सूचकांक, बायां मान; हजार करोड़, दायां मान)



*: आंकड़े 20 जुलाई 2026 तक के है।
टिप्पणी: डीआईआई: घरेलू संस्थागत निवेशक; एफ़पीआई: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक।
स्रोत: ब्लूमबर्ग।

[66] अप्रैल-मई 2026 के दौरान, निवल एफ़डीआई 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में था। इसी तरह, सकल आवक एफ़डीआई बढ़कर 17.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 21.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। हालांकि, मई 2026 में, निवल एफ़डीआई मई 2025 के 0.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर (-) 0.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

चार्ट IV.11 अप्रैल-मई 2026 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सुधार देखा गया।



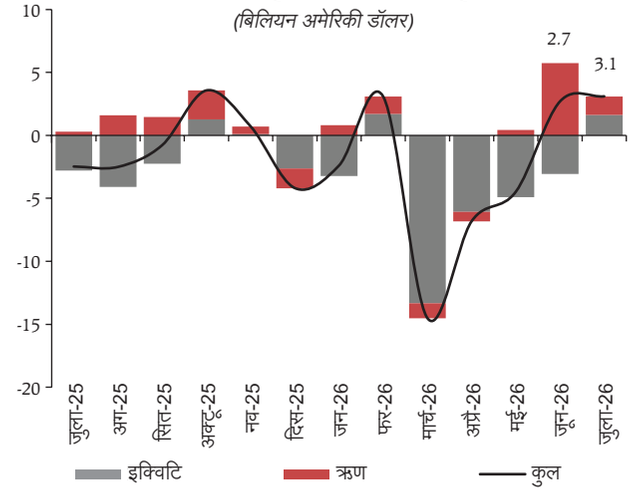
स्रोत : *आरबीआई।*

इन क्षेत्रों की कुल अंतर्वाह में हिस्सेदारी लगभग 80 प्रतिशत रही। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई) के बहिर्प्रवाह का लगभग 74 प्रतिशत अमेरिका, केमैन द्वीप समूह और नीदरलैंड की ओर निर्देशित रहा; प्रमुख क्षेत्रों में वित्तीय, बीमा और व्यावसायिक सेवाएं, और विनिर्माण शामिल थे, जिनका अप्रैल-मई 2026 के दौरान कुल बहिर्प्रवाह में 85 प्रतिशत से अधिक योगदान था (चार्ट IV.11बी)।

जून 2026 के दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में निवल आवक दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण ऋण खंड के लिए नीतिगत समर्थन और भू-राजनीतिक तनावों का कम होना था।[67] जुलाई में (20 जुलाई तक), एफ़पीआई ने शेयर और ऋण खंडों में कुल 3.1 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया (चार्ट IV.12)।

पिछले वर्ष की तुलना में अप्रैल-मई 2026 के दौरान बाहरी वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।[68] मूलधन चुकौती को समायोजित करने के बाद, निवल ईसीबी अंतर्वाह कम रहा। हालांकि, मई 2026 में निवल ECB अंतर्वाह में क्रमिक विस्तार दर्ज किया गया (चार्ट IV.13)।[69] लगभग 37 प्रतिशत ईसीबी पूंजीगत व्यय के लिए जुटाए गए थे।

चार्ट IV.12: जुलाई में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने का प्रवाह लगातार बना रहा।



*: 20 जुलाई 2026 तक के आंकड़े।
टिप्पणी: डेट में हाइब्रिड लिखत के तहत निवेश भी शामिल हैं।
स्रोत: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)।

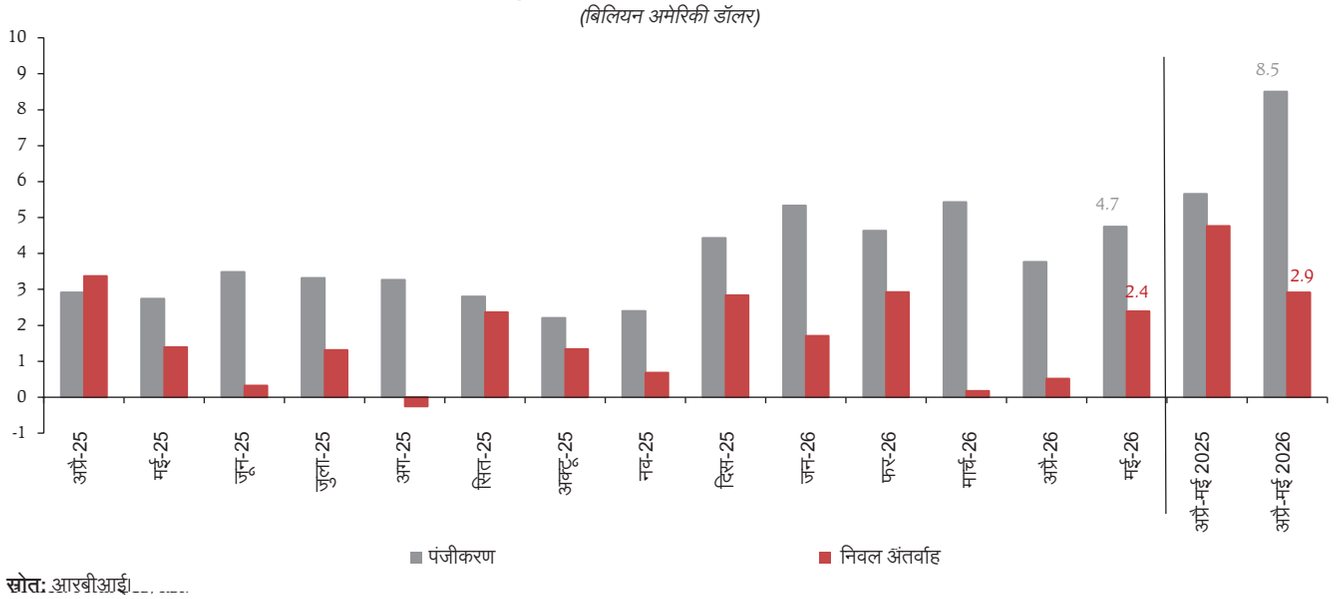
[67] जून 2026 के दौरान, एफ़पीआई ने 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल अंतर्वाह दर्ज किए, जो जून 2025 में 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। 2026-27 के दौरान अब तक (20 जुलाई, 2026 तक), एफ़पीआई ने 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल बहिर्वाह दर्ज किए, जो मुख्य रूप से इक्विटी सेगमेंट से निकासी के कारण हुए।

[68] अप्रैल-मई 2026 के दौरान कुल ईसीबी पंजीकरण 8.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ गए, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 5.7 अरब अमेरिकी डॉलर था।

[69] नेट ईसीबी प्रवाह अप्रैल-मई 2026 में 2.9 अरब अमेरिकी डॉलर पर कम रहे, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 4.8 अरब अमेरिकी डॉलर था। नेट ईसीबी प्रवाह मई 2026 में 2.4 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ गए, जबकि पिछले महीने यह 0.5 अरब अमेरिकी डॉलर था।

चार्ट IV.13: बाह्य वाणिज्यिक उधार – पंजीकरण और प्रवाह

(बिलियन अमेरिकी डॉलर)



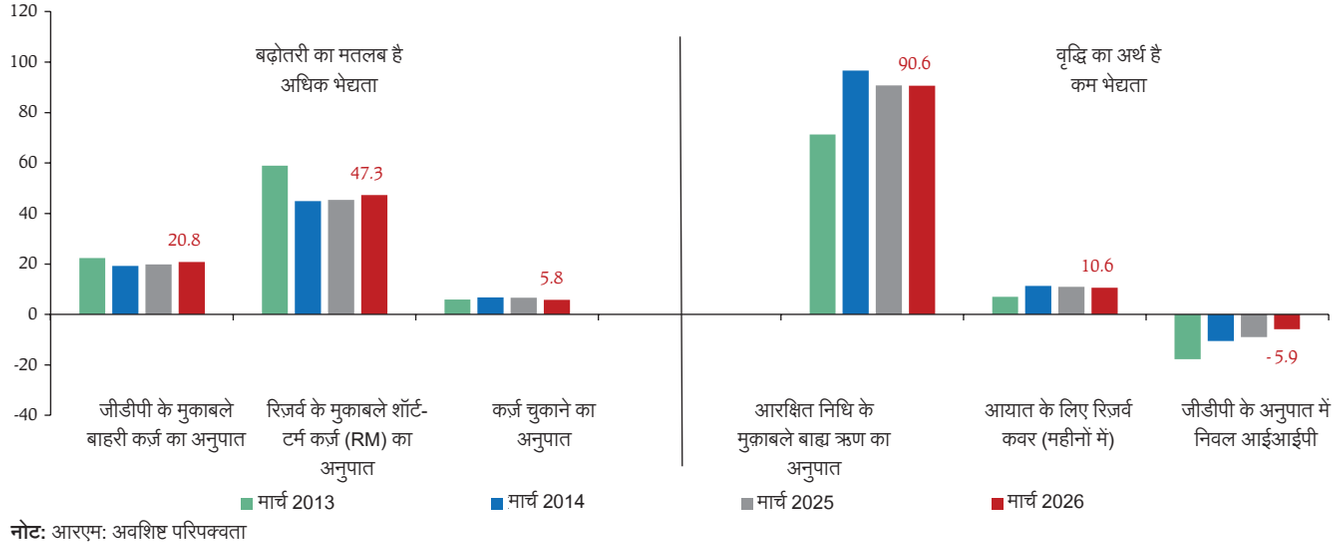
स्रोत: आरबीआई।

पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अप्रैल-मई 2026 में अनिवासी जमा (एनआरडी) के तहत निवल प्रवाह में कमी आई, जिसका मुख्य कारण अनिवासी बाह्य रुपया खाता [एनआर(ई)आरए] और विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक [एफ़सीएनआर(बी)] खातों में मंदी रही। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा एनआरडी, विदेशी मुद्रा ऋण (ओएफ़सीबी) और ईसीबी अंतःप्रवाह पर हाल ही में उठाए गए नीतिगत कदमों, जिनमें 5 जून, 2026 को नए एफ़सीएनआर(बी) जमा के लिए रियायती स्वैप सुविधा भी शामिल है, के परिणामस्वरूप 8 जून से 17 जुलाई, 2026 के बीच एफ़सीएनआर(बी) जमा अंतःप्रवाह में 17.4 अरब अमेरिकी डॉलर की भारी वृद्धि दर्ज की गई।[70]

मार्च 2026 के अंत तक बाहरी क्षेत्र की प्रमुख कमज़ोरी के संकेतक, यानी बाहरी ऋण-से-जीडीपी अनुपात, निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (एनआईआईपी) से जीडीपी अनुपात,

चार्ट IV.14: भारत के बाह्य संवेदनशीलता संकेतक नियंत्रित रहे

(प्रतिशत)



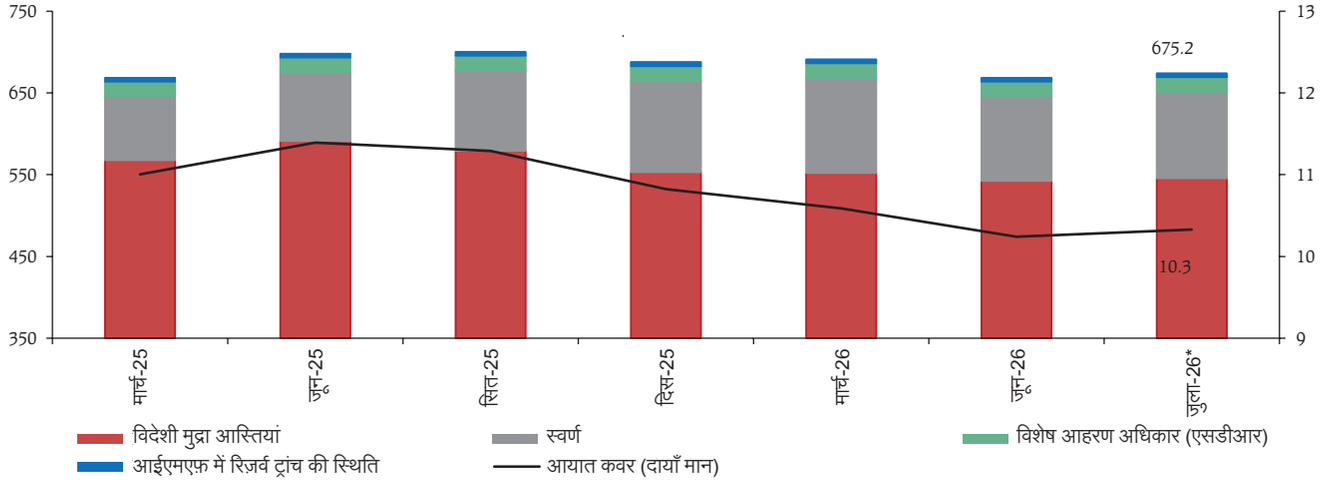
नोट: आरएम: अवशिष्ट परिपक्वता

स्रोत: आरबीआई।

[70] इसी अवधि में, ओएफसीबी और ईसीबी को क्रमशः 1.97 अरब अमेरिकी डॉलर और 1.34 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रवाह दर्ज किया गया।

चार्ट IV.15: भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त बना रहा

(बिलियन अमेरिकी डॉलर, बायां मान; माह की संख्या, दायां मान)



टिप्पणी : 1. *: 10 जुलाई, 2026 तक।
2. आयात कवर डेटा भुगतान संतुलन सांख्यिकी के अनुसार वार्षिक पण्य वस्तु आयात पर आधारित है।

स्रोत: आरबीआई।

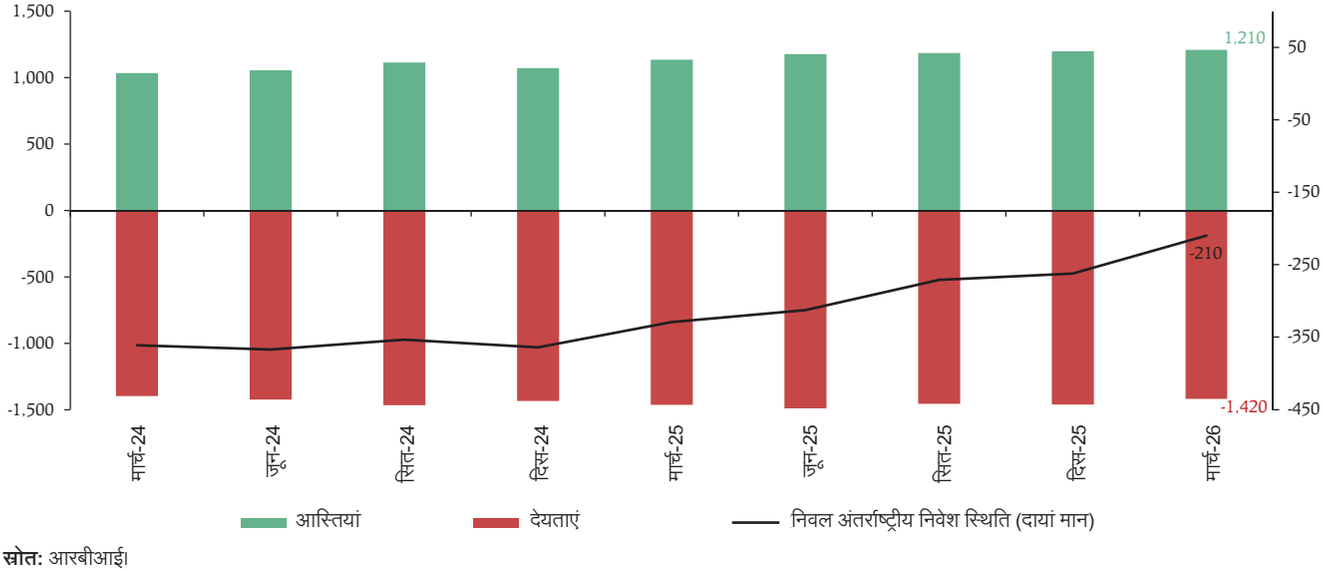
ऋण सेवा अनुपात और विदेशी मुद्रा भंडार के मुकाबले अल्पकालिक ऋण (अवशिष्ट परिपक्वता) नियंत्रण में रहे (चार्ट IV.14)। मार्च 2026 के अंत में भारत का बाहरी ऋण 762.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया।[71]

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त स्तर पर बना हुआ है, जो मार्च 2026 के अंत की स्थिति के अनुसार 10 महीने[72] से अधिक के वस्तुओं के आयात और कुल बाहरी ऋण के लगभग 88.5 प्रतिशत[73] को सुरक्षा प्रदान करता है (चार्ट IV.15)।

वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की एनआईआईपी बेहतर हुई, जिसका मुख्य कारण भारत की विदेशी देनदारियों

चार्ट IV.16: भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति में सुधार हुआ है

(बिलियन अमेरिकी डॉलर, बायां मान; बिलियन अमेरिकी डॉलर, दायां मान)



स्रोत: आरबीआई।

[71] यह मार्च 2025 के अंत में 736.4 अरब अमेरिकी डॉलर था।

[72] 10 जुलाई, 2026 को, वस्तुओं और सेवाओं के लिए आयात कवर लगभग 8.2 महीने का था।

[73] यह गणना 10 जुलाई, 2026 की स्थितियों के अनुसार की गई है।

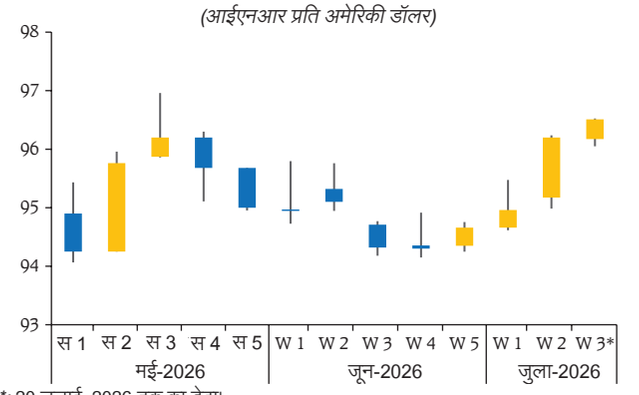
में कमी और विदेशी परिसंपत्तियों में वृद्धि रहा (चार्ट IV.16)।[74] विदेशी देनदारियों में गिरावट भारत में पोर्टफोलियो और प्रत्यक्ष निवेश में कमी तथा इस तिमाही के दौरान प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपये (आईएनआर) के मूल्यह्रास के प्रभाव को दर्शाती है।[75]

विदेशी मुद्रा बाज़ार

सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए कदमों के कारण विदेशी निवेश में सुधार और कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय दामों में गिरावट के चलते जून के महीने में भारतीय रुपये में मजबूती आई। अन्य प्रमुख उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं के अनुरूप, अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के कारण जुलाई (20 तारीख तक) में लाभ में कमी आई (चार्ट IV.17)। वास्तविक प्रभावी संदर्भ में, नाममात्र प्रभावी संदर्भ में भारतीय रुपये की मजबूती और उच्च घरेलू मुद्रास्फीति के कारण, जून में भारतीय रुपया अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के मुकाबले मजबूत हुआ (चार्ट IV.18)।

चार्ट IV.17: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में उतार-चढ़ाव

(आईएनआर प्रति अमेरिकी डॉलर)



*: 20 जुलाई, 2026 तक का डेटा।

टिप्पणी: 1. डबल्यू का मतलब है कैलेंडर सप्ताह, जो हर महीने की 1-7, 8-14 जैसी तारीखों से शुरू होते हैं।

2. नीली कैंडल बढ़त दिखाती हैं, यानी सप्ताह के आखिर में भारतीय रुपये की कीमत सप्ताह के शुरुआत में खुलने के समय की तुलना में कम रही। पीली कैंडल गिरावट दिखाती हैं, यानी सप्ताह के आखिर में भारतीय रुपये की कीमत सप्ताह के आरंभ में खुलने के समय की तुलना में ज़्यादा रही।

स्रोत: रिफाइनिटिव; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

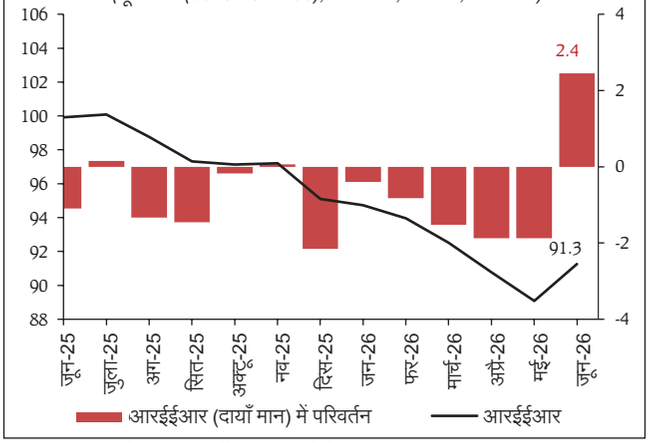
V. निष्कर्ष

वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चित आर्थिक परिवेश, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और खंडित व्यापारिक संबंधों से जूझ रही है। इन अनिश्चितताओं के बीच, भारत दुनिया भर की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं[76] में शामिल है और जून तक आर्थिक गतिविधियों में गति बनाए रखने में सफल रहा है। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र दोनों के संकेतक मज़बूत बने रहे। कृषि

चार्ट IV.18: जून में वास्तविक प्रभावी विनिमय दर के आधार पर रुपया मजबूत

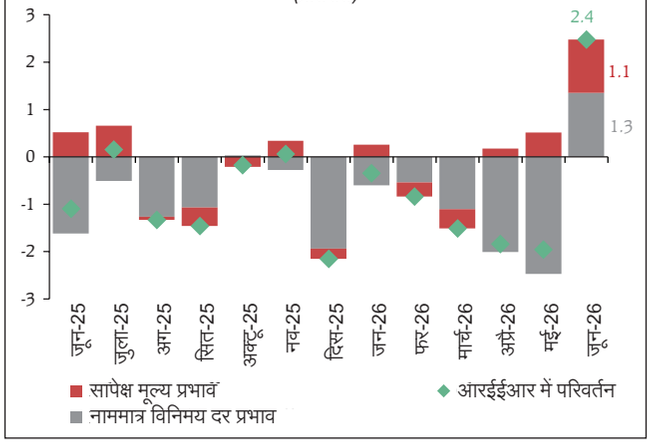
ए. मासिक परिवर्तन

(सूचकांक (2015-16 = 100), बायां मान; प्रतिशत, दायां मान)



बी. मासिक परिवर्तनों का अपघटन

(प्रतिशत)



टिप्पणी: 1. आरईईआर: वास्तविक प्रभावी विनिमय दर।

2. सकारात्मक बदलाव नामिक और वास्तविक विनिमय दर में बढ़ोतरी दिखाता है और नकारात्मक बदलाव अवमूल्यन दिखाता है।

स्रोत: आरबीआई।

[74] नेट आईआईपी 52.4 अरब अमेरिकी डॉलर की बढ़त के साथ मार्च 2026 के अंत में (-) 209.9 अरब अमेरिकी डॉलर पर खड़ा था।

[75] मार्च 2026 के अंत में भारत की अंतरराष्ट्रीय संपत्तियों और अंतरराष्ट्रीय देनदारियों का अनुपात 85.2 प्रतिशत तक सुधरा, जबकि दिसंबर 2025 के अंत में यह 82.0 प्रतिशत था।

[76] आईएमएफ की वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक अपडेट, जुलाई 2026।

क्षेत्र में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की स्थिति असमान है, परंतु खाद्य मुद्रास्फीति पर इसका प्रभाव पर्याप्त खाद्यान्न भंडार के कारण कम हो सकता है। बाहरी व्यापार की गति बरकरार रही, जैसा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में निर्यात और आयात की उच्च वृद्धि से झलकता है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के हालिया क्रियान्वयन तथा अन्य द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में प्रगति से इसके और अधिक मजबूत होने की संभावना है। बाहरी संवेदनशीलता के संकेतक भी सुदृढ़ बने रहे। पिछले कुछ महीनों में विदेशी निवेश में सुधार अर्थव्यवस्था में विश्वास की बहाली को दर्शाता है।

अनुलग्नक

बॉक्स 1: थोक मूल्य सूचकांक (डबल्यूपीआई) के आधार वर्ष का 2011-12 से 2022-23 में संशोधन

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 कर दिया गया है। 15 जून 2026 को मई 2026 के अनंतिम आंकड़ों के साथ नई श्रृंखला तथा अप्रैल 2023 से अप्रैल 2026 तक की पिछली श्रृंखला जारी की गई। इस संशोधन के फलस्वरूप, डबल्यूपीआई का आधार वर्ष 2022-23 सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) की संशोधित श्रृंखला के अनुरूप हो गया है।

संशोधित थोक मूल्य सूचकांक में वस्तुओं की संख्या पिछले आधार वर्ष के 697 से बढ़कर 957 हो गई है, जबकि प्रमुख समूहों का भारांक लगभग समान ही है (सारणी 1)।

सारणी 2 में संशोधित आधार वाले थोक मूल्य सूचकांक (डबल्यूपीआई) की पिछले वाले से तुलना प्रस्तुत की गई है।

सारणी 1: डब्ल्यूपीआई - मदें और भारांश

समूह/श्रेणी	डबल्यूपीआई (2011-12)		डबल्यूपीआई (2022-23)	
	मदें	भार	मदें	भार
प्राथमिक वस्तुएं	115	22.62	129	22.76
ईंधन और बिजली	18	13.15	25	14.11
निर्मित वस्तुएं	564	64.23	803	63.13
कुल	**697**	**100**	**957**	**100**

वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करते हुए, डबल्यूपीआई से उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई) में क्रमिक बदलाव होगा। जून 2026 से निर्गत पीपीआई, आगत पीपीआई (प्रायोगिक आधार पर) और सेवा उत्पादक मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी करना भी शुरू हो गया है।

सारणी 2: संशोधित डब्ल्यूपीआई श्रृंखला और पूर्ववर्ती आधार श्रृंखला की तुलना

पैरामीटर	डबल्यूपीआई (आधार 2011-12)	डबल्यूपीआई (आधार 2022-23)
भार का निर्धारण	निवल ट्रेडेड वैल्यू (एनटीवी) यानी उत्पादन के सकल मूल्य (जीवीओ) + आयात-निर्यात के दृष्टिकोण पर आधारित।	यह वैश्विक स्तर पर स्वीकृत और अधिक सटीक जीवीओ दृष्टिकोण पर आधारित है, जो घरेलू उत्पादक के दृष्टिकोण से आर्थिक महत्व को दर्शाता है।[77]
प्राथमिक सूचकांक की गणना	लंबी अवधि की निर्माण विधि, जिसमें वर्तमान कीमतों की तुलना सीधे निश्चित आधार अवधि की कीमतों से की जाती है।	श्रृंखला-आधारित जेवन्स पद्धति का उपयोग करते हुए अल्पकालिक सूत्रीकरण, जो चालू महीने की कीमतों की तुलना पिछले महीने की कीमतों से करता है।
अनुपलब्ध मूल्य उपचार	पुरानी 'कैरी-फ़ॉरवर्ड' पद्धति पर निर्भर रहते हुए, पिछली उपलब्ध कीमत को दोहराया गया।	यह 'लक्षित माध्य अनुमान' पद्धति का उपयोग करता है, जो समान उपलब्ध विशिष्टताओं के मूल्य परिवर्तनों के ज्यामितीय माध्य के आधार पर लापता मूल्य का अनुमान लगाता है।
कच्चा तेल और गैस वर्गीकरण	इसे 'प्राथमिक वस्तुएं' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।	प्राथमिक ऊर्जा क्षेत्र की ट्रैकिंग को समेकित और एकीकृत करने के लिए 'फ्यूल एंड पावर' समूह में स्थानांतरित किया गया।
विद्युत कवरेज और संरचना	बास्केट में पारंपरिक बिजली स्रोतों को एक समेकित मद के रूप में ट्रैक किया गया।	इसे पाँच अलग-अलग बिजली उत्पादन स्रोतों में विभाजित किया गया है: जलविद्युत, तापविद्युत, परमाणु, सौर और पवन।
कोयला मूल्य निर्धारण तंत्र	कोयले की मुद्रास्फीति को ट्रैक करने के लिए केवल अधिसूचित कीमतों का उपयोग किया गया।	इसमें कोकिंग और गैर-कोकिंग कोयले की नीलामी (एक्सचेंज के माध्यम से) और अधिसूचित कीमतें दोनों शामिल हैं।
कैप्टिव खदानों का संचालन	कैप्टिव खदानों की खदान-द्वार कीमतें शामिल थीं।	इसमें कैप्टिव खदानों की कीमतें शामिल नहीं हैं (चूँकि उनका उत्पादन आंतरिक उपयोग के लिए होता है, खुले बाज़ार में बेचने के लिए नहीं), सिवाय तांबे, सीसे और जस्ते के, क्योंकि इनका डेटा उपलब्ध नहीं है।

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।

[77] पुरानी डबल्यूपीआई श्रृंखला में नेट ट्रेडेड वैल्यू दृष्टिकोण का उपयोग किया गया था, जिसमें उच्च मात्रा/वॉल्यूम में आयात किए गए वस्त्रों का वजन अधिक हो सकता है, भले ही घरेलू उत्पादन कम हो; इसी प्रकार, बड़ी मात्रा/वॉल्यूम में उत्पादन की गई वस्त्रों का वजन कम हो सकता है यदि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निर्यात किया जाता है। वस्त्रों और सेवाओं के उत्पादक को प्राप्त वास्तविक राजस्व को प्रतिबिंबित करने के लिए, संशोधित डबल्यूपीआई श्रृंखला में बुनियादी कीमतों पर आउटपुट के मूल्य (सकल आउटपुट मूल्य या जीवीओ के समकक्ष) का उपयोग भार के रूप में किया गया है, जो आईएमएफ मैनुअल की सिफारिशों के अनुरूप है।